जनवरी, 2024, वर्ष : 45 अंक : 01 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

# तिब्बत देश

## बारहवें एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन ने परम पावन दलाई लामा को 'बौद्ध धर्म का वैश्विक सर्वोच्च धर्मगुरु' घोषित किया

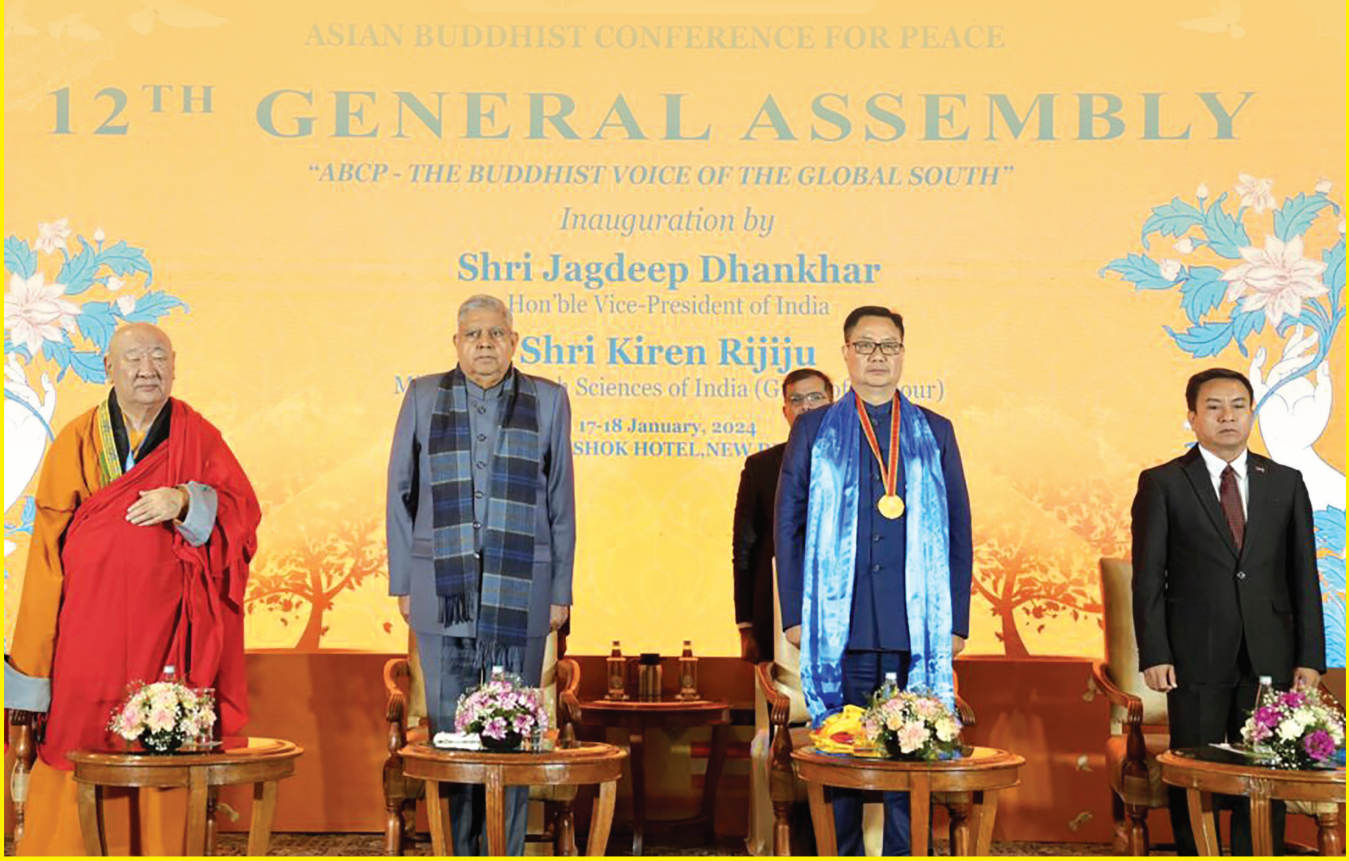


मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

जनवरी, 2024, वर्ष : 45 अंक : 01

# तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७५वां गणतंत्र दिवस मनाया

**प्रधान संपादक**
**जमयंग दोरजी**

**सलाहकार संपादक**
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

**प्रबंध संपादक**
तेनजिन जोरदेन

**वितरण प्रबंधक**
**ताशी देकि**

**संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :**
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

## समाचार -


- गेलुक्पा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 1
- बारहवें एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन ने परम पावन दलाई लामा को 'बौद्ध धर्म का वैश्विक सर्वोच्च धर्मगुरु' घोषित किया 2
- जापान में भूकंप को लेकर परम पावन का संदेश 3
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को बधाई दी 4
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७५वां गणतंत्र दिवस मनाया 5
- सिक्योंग पेन्पा ने एस्टोनियाई संसद में 'तिब्बत की वैधानिक स्थिति' पर सुनवाई में भाग लिया 6
- तिब्बती छात्रों को बाहर से पढ़ाई करने पर प्रतिबंध अपराधियों को ढूंढने के लिए रात-दिन जांच की जा रही है। 7
- तिब्बत के बौद्ध मठों में किसी नए भिक्षु के प्रवेश की अनुमति नहीं सूत्रों का कहना है कि यह कदम धार्मिक गतिविधियों पर चीन के कठोर नियंत्रण को दर्शाता है। 8
- सिक्योंग ने तिब्बत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लैटिवियन पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों से मुलाकात की 9
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने लिथुआनियाई संसद में ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहे तिब्बत की वकालत की 10
- २०२३ में तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति, एक वर्ष की समीक्षा 11


## समाचार -


- संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन की समीक्षा में सदस्य देशों द्वारा तिब्बती अधिकारों को अभूतपूर्व समर्थन, बीजिंग ने आलोचना पर चुप्पी साधी 12
- मैनपाट तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी के नेतृत्व में सामुदायिक प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री से मुलाकात की 13
- चीनी संपर्क अधिकारी छुल्ट्रीम ग्यात्सो ने 'अहिंसक प्रतिरोध, हाई-टेक अधिनायकवाद और चीन का भविष्य' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया 14
- तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों ने कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तिब्बती कल्याण जारी रखने का आग्रह किया 15
- तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की, तिब्बत के पक्ष में बात की 16
- कैलाश शिखर के पास चीन का नया बांध भारत के लिए खतरा? 17
- तिब्बत का सफाया : चीन की नवीनतम भाषाई लड़ाई 18
- नास्तिक चीन को दलाई लामा के पुनर्जन्म मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए 19

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
coordinator@indiatibet.net

**अपनी बात**

# ◆ संसार की छत एवं तीसरे ध्रुव तिब्बत में चिंताजनक पर्यावरण-संकट

परमपावन दलाईलामा ने कालचक्र मैदान, बोधगया से नववर्ष 2024 की शुभकामना दी है। वे वहाँ आध्यात्मिक प्रवचन, पूजा-पाठ तथा धर्मोपदेष हेतु पधारे हैं। अपने शुभकामना संदेष में उन्होंने सभी के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाया है। प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण के संरक्षण से ही मानवकल्याण संभव है। प्राकृतिक संसाधनों के विनाष एवं पर्यावरण के प्रदूषण से सम्पूर्ण सृष्टि को खतरा है। इस प्रकार दलाईलामा का स्पष्ट विचार है कि हम सम्पूर्ण विष्व के कल्याण में मनुष्य के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के कल्याण को भी रचनात्मक स्थान दें।

दलाईलामा बौद्ध धर्मगुरु हैं। बौद्ध परंपरा में नववर्ष को लोसर कहा जाता है। यह सामान्यतः फरवरी माह में आता है। सभी बौद्ध मतावलंबी लोसर उत्साहपूर्वक मनाते हैं। वे उस अवसर पर भगवान् बुद्ध की विषेष पूजा-अर्चना करते हैं, पारंपरिक नाच-गान करते हैं, घरों एवं अन्य स्थानों की आकर्षक सजावट करते हैं, निःषुल्क भंडारे चलाते हैं तथा गरीबों को वस्त्रादि देते हैं। उस समय दलाईलामा के दीर्घजीवन हेतु विषेष पूजा-प्रार्थना की जाती है। फिर प्रष्न है कि दलाईलामा अंग्रेजी नववर्ष की बधाई क्यों देते हैं? हम जिस विष्व में हैं उसमें प्रतिवर्ष कई नववर्ष होते हैं। अकेले अपने भारत में ही कई नववर्ष हैं। ये विभिन्न आध्यात्मिक पंथों (रिलिजन), व्यवसायों, मौसम तथा कई मान्यताओं पर आधारित हैं। इसीलिये समाज में कई प्रकार के पंचांग (कैलेंडर) हैं। सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को बढ़ाने के लिये हमें विभिन्न नववर्षों से जुड़े उत्सवों से स्वयं को जोड़ना चाहिये। दलाईलामा इसी के उदाहरण हैं। उनके लिये लोसर के समान ही अंग्रेजी नववर्ष है।

शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दलाईलामा विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। बौद्ध दर्षन में लोगों की बढ़ती रुचि का यह ठोस प्रमाण है। दलाईलामा बौद्ध मतावलंबी होने के कारण बौद्ध दर्षन का भरपूर प्रचार-प्रसार करते हैं लेकिन हर समय वे अन्य संप्रदायों (रिलिजन, मत, पंथ, मजहब) एवं उनके अनुयायियों का भी सम्मान करते हैं। अपने प्रवचनों में वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। उनके इसी आचार-विचार-व्यवहार का परिणाम है कि बौद्ध दर्षन में लोगों की रचनात्मक रुचि बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं कि प्रत्येक रिलिजन में मानवीय मूल्यों पर जोर है। सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भाव तथा सहयोग मानवीय मूल्य हैं। हम इन मूल्यों को मजबूत करें। इसी से समाज में सांप्रदायिक सद्भाव आयेगा। अपनी-अपनी पूजा पद्धति का पालन करें तथा अन्य पूजा-पद्धति का सम्मान करें। यही है सर्वपंथ समादरभाव अर्थात् सेकुलरिजम।

नववर्ष 2024 में हमें तिब्बती संघर्ष को ठोस परिणाम तक पहुँचाना है। इस कार्य में तिब्बतियों के साथ अनेक तिब्बत समर्थक संगठन एवं व्यक्ति सक्रिय हैं। विष्व के विभिन्न देषों में तिब्बती संघर्ष के प्रति सहयोग एवं समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसे और सुव्यवस्थित तथा परिणामदायक बनाना है। वर्ष 1959 में साम्राज्यवादी चीन ने स्वतंत्र देष तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कर लिया था। तिब्बत समर्थक चाहते हैं कि तिब्बत को पूर्ण आजादी मिले। चीन को तिब्बत से बाहर निकाला जाये। इसके विपरीत तिब्बती, निर्वासित तिब्बत सरकार तथा दलाईलामा की मांग है कि तिब्बत को पूर्ण आजादी की जगह चीन के अंदर ही "वास्तविक स्वायत्तता" मिले। तथाकथित स्वायत्तता अभी भी है। इसके नाम पर चीन सरकार ने तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्र में काट-छाँट कर उसे चीनी भूभाग का अंग बना लिया है। तिब्बत का चीनीकरण जारी है। तिब्बती पहचाने मिटाने का षड्यन्त्र जारी है। इसीलिये "वास्तविक स्वायत्तता" की मांग हो रही है।

चीनी संविधान और राष्ट्रीयता संबंधी कानूनों के अनुरूप चीनी संप्रभुता एवं भौगोलिक एकता-अंखडता की रक्षा करते हुए तिब्बत को अधिकार मिले। चीन के पास प्रतिरक्षा तथा विदेष विभाग हों। षिक्षा, कृषि सहित अन्य विषय तिब्बतियों को मिलें। यही है मध्यममार्ग। तिब्बती मानते हैं कि तिब्बत की आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है तिब्बती पहचान का संरक्षण। खुषी की बात है कि सभी तिब्बत समर्थक तिब्बतियों की इस "मध्यममार्ग" नीति से सहमत हैं। वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तिब्बती संघर्ष के साथ हैं।

चीन सरकार के साथ दलाईलामा एवं निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता पुनः प्रारम्भ हो। इस हेतु चीन सरकार पर दबाव बढ़ाने तथा उपयुक्त वातावरण बनाने की दिषा में विष्व जनमत सक्रिय है। उपनिवेषवादी चीन सरकार की धमकियों की उपेक्षा कर कई देष दलाईलामा को सम्मानित-पुरस्कृत कर रहे हैं। वे अपनी संसद में उनके उद्बोधन सुन रहे हैं। वे तिब्बती समाज की मदद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि विष्व की छत अर्थात् विश्व के तीसरे ध्रुव अर्थात् तिब्बत संकट का हल शीघ्र निकले। तिब्बत, जो कि एषिया का वाटर टावर है, संकटग्रस्त है, क्योंकि यहाँ के ग्लेसियर (हिमनद) सिकुड़ते-सूखते जा रहे हैं।

भोगवादी चीन सरकार साजिसपूर्वक तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है। तिब्बती क्षेत्र में रेडियोधर्मी खतरनाक परमाणु कचरा गाड़ा जाता है। इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह पूरे विष्व के लिये चिंता एवं चिंतन का विषय है। उपनिवेषवादी चीन सरकार की तिब्बत नीति का विरोध विष्व स्तर पर जारी है। मानवाधिकारों, अंतरराष्ट्रीय कानून, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवीय आदर्षों का क्रूरतापूर्ण हनन चीन की विषेषता है। तिब्बत इसी का षिकार है। अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन इस तथ्य को प्रकाषित-प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। इस नववर्ष में तिब्बती सवाल के समाधान की दिषा में निर्णायक प्रगति होगी, इसी मंगलकामना के साथ नववर्ष की पुनः बधाई।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

# ◆ गेलुक्पा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह

dalailama.com, ०३ जनवरी २०२४

**बोधगया, बिहार, भारत।** परम पावन दलाई लामा को ०३ जनवरी की सुबह गेलुक्पा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने और पिछले चार वर्षों के दौरान स्नातक करने वाले गेशेस को गेशे ल्हारम्पा डिग्री प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कालचक्र मैदान के द्वार पर दक्षिण भारत में- गैंडेन, डेपुंग और सेरा जैसे शिक्षा के महान केंद्रों के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया और उन्हें मंच तक ले गए। मंच पर परम पावन बीच में बैठे। उनकी दाहिनी ओर गैंडेन त्रि रिनपोछे और बायीं ओर जांगछे छोजे रिनपोछे थे।

मंच पर समारोह के संचालक गेशे तुल्कु तेनज़िन शेरब ने परम पावन के साथ ही अन्य अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि तिब्बत पर १९५९ में हुए चीनी हमले के बाद परम पावन के आशीर्वाद से हजारों तिब्बती भारत पहुंच पाए। इस हमले के दौरान तिब्बत में अधिकांश बौद्ध परंपरा को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद मठवासी बक्सादुआर के एक शिविर में एकत्रित हुए, जहां, परम पावन और उनके दो शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक गेशे लाराम परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इस बीच तीन महान मठ विश्वविद्यालयों से जुड़े भिक्षुओं ने अध्ययन की परंपरा को बनाए रखा। मॉडरेटर ने घोषणा की कि इन सबको नेतृत्व और प्रेरणा देने में परम पावन ने जो करुणा बरसाई है, उस ऋण को कभी नहीं चुकाया जा सकता है।

१९७० में एक गेलुक्पा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें मठाधीश और परीक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने प्रक्रियाएं और नियम बनाए। तब से १००० से अधिक गेशे स्नातक हो चुके हैं। उनमें से कई लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धर्म की सेवा कर रहे हैं।

सबसे पहले गैंडेन त्रि रिनपोछे को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, 'बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु परम पावन दलाई लामा आज यहां हमारे साथ हैं। यहां हम गेलुक्पा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और डिग्री वितरण समारोह में एकत्र हुए हैं। आज स्नातक होने वालों ने पूरी तरह से अध्ययन किया है, तर्क और बहस का अभ्यास किया है और अपनी परीक्षा दी है। परिणामस्वरूप, उन्हें अपनी ल्हारम्पा डिग्री प्राप्त होगी। जैसा कि जे रिनपोछे ने सलाह दी है, हमें जो सीखा है उसका अध्ययन, चिंतन और एकीकरण करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'एक बार जब आप गेशे डिग्री हासिल कर लेते हैं तो गुह्यसमाज की चार टीकाओं का अध्ययन करने के लिए ग्युडमे या ग्यूडटो तांत्रिक कॉलेज में नामांकन लेने का रिवाज है। यह एक परंपरा है जो ज़े रिनपोछे के समय से बिना किसी रुकावट के चली आ रही है। नए-नए स्नातक हुए गेशे द्वारा अध्ययन किए जाने वाले और भी ग्रंथ हैं, लेकिन जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वह गुह्यसमाज टीका के पठन पाठन और उसका लोगों में प्रसार करना है। मैं आप सभी से इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह करता हूं। जैसा कि सेरखोंग छेनशाब रिनपोछे कहा करते थे, इस परंपरा को जीवित रखना आवश्यक है।'

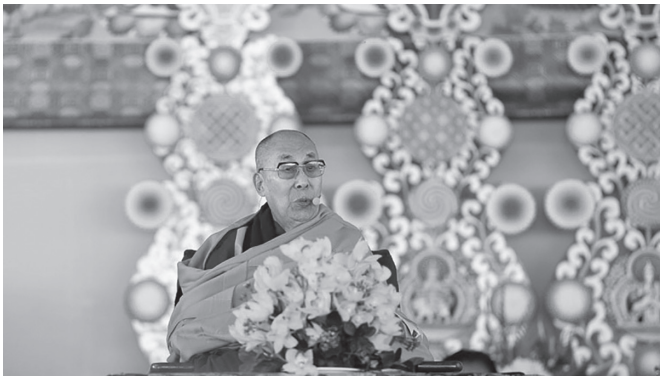

मैं प्रार्थना करता हूं कि परम पावन दलाई लामा और हमारी अन्य सभी बौद्ध परंपराओं के नेता लंबे समय तक जीवित रहें।

परम पावन ने घोषणा की, 'आज मोनलम चेन्मो या महान प्रार्थना महोत्सव का समापन होता है। यहां उपस्थित हम सभी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षा प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने के बारे में नहीं है। यह मुख्य रूप से बोधिचित्त और शून्यता में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए हमारे दिमाग का उपयोग करने के बारे में है।

बौद्ध भिक्षु होने के कारण मैं सुबह उठते ही जागृत मन और शून्यता का चिंतन-मनन करता हूं। इस तरह मेरा दिन इन सिद्धांतों से ओत-प्रोत होता है। बोधिचित्त के चिंतन से मुझे अपने और दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने का आशीर्वाद देने का संकल्प हो जाता है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी भव्य जीवों को अपने अतिथि के रूप में आह्वान करता हूं।

मैं बोधिचित्त को शून्यता के दृष्टिकोण से जोड़ने की भी पूरी कोशिश करता हूं। यह दृष्टिकोण मानसिक कष्टों और दुख देने वाली अवधारणाओं पर काबू पाने का तरीका है। मानसिक कष्ट और दुख देने वाली अवधारणाएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे अज्ञानता से लिप्त हैं और इसलिए आधारहीन हैं। दूसरी ओर बोधिचित्त और शून्यता अधिक शक्तिशाली हैं और कारणयुक्त और तर्कनिष्ट हैं।

इसलिए जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना अधिक हम अंतर्दृष्टि और अनुभव प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म तार्किक और तर्कसंगत है। जैसा कि 'बोधिसत्व मार्ग में प्रवेश' ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्ञात होने से आसान न हो जाए। जितना अधिक हमें शून्यता का ज्ञान होता जाता है, उतना ही हमारा अज्ञान कम होता जाता है।'

मैं रोज बोधिचित्त और शून्यता का एकीकृत चिंतन करने की साधना करता हूं और इसका परिणाम भी देखता हूं। देव योग महत्वपूर्ण है, लेकिन बोधिचित्त और शून्यता की समझ विकसित कर लेना और भी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे इन परंपराओं को सही मायने में अपनाने का आग्रह करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे आपको सहज महसूस कराएंगे। बोधिचित्त और शून्यता ही जीवन को सार्थक बनाती है। बोधिचित्त और शून्यता के अभाव में केवल देव योग में संलग्न होने से कुछ नहीं होगा।

आज जब आप ल्हारम्पा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करना अतुलनीय है। यह तिब्बत के लिए कुछ खास है। मेरे कई अन्य बौद्ध देशों में मित्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमारी तरह अध्ययन करते हैं। मेरी अपनी पढ़ाई तब

शुरू हुई जब मैं छोटा बच्चा था। जैसा कि मैंने आपको दूसरे दिन बताया था। जब मैं लगभग तीन साल का था, उस समय मैंने कुंबुम मठ का दौरा किया था और युवा भिक्षुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए 'ओम अरा पतसा ना दिह' का पाठ करते हुए देखकर और उनकी आवाज सुनकर दंग रह गया था। मैं उनकी नकल करने के लिए प्रेरित हुआ। उमर होने पर मैं अपनी औपचारिक पढ़ाई के लिए मध्य तिब्बत गया। पढ़ाई में सामूहिक विषय, मन और जागरूकता, कारण और तर्क का अध्ययन शामिल था। इन अध्ययनों को जिस चीज़ ने प्रभावी ढंग से समेकित किया वह था वाद-विवाद का अभ्यास।

हम दुनिया की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं। हम अपने सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन मंजुश्री हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हमारी बुद्धि को मजबूत करेगी। अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।'

मॉडरेटर ने बताया कि आज के दीक्षांत समारोह में ३०० से अधिक गेशे स्नातक मंच पर उपस्थित होंगे जहां गैंडेन त्रि रिनपोछे उन्हें स्नातक डिग्री प्रदान करेंगे। इसके बाद जब ये गेशे स्नातक मंच पर पहुंचे तो उनके गले में सफेद रेशमी खटक (स्कार्फ) लिपटी हुई थी। डिग्री ग्रहण करने के बाद प्रत्येक गेशे ने मंच छोड़ने से पहले परम पावन के सामने सिर नवाया।

इसके बाद पिछले चार वर्षों में स्नातक करने वाले गेशे के समूह ने वर्ष के आधार पर परम पावन के साथ तस्वीरें खिंचाने को उनके आसपास एकत्र हुए।

परम पावन ने सभा से एक बार फिर बात करने की इच्छा व्यक्त की।

'ज़े रिनपोछे ने हमें बताया कि हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं, उसे वास्तव में समझने के लिए हमें चार स्तर के तर्क करने की आवश्यकता है। हम किसी चीज़ के संबंध में पूछ सकते हैं- 'क्या यह एक कण है? या यह एक कण नहीं है? क्या यह कण है भी और कण नहीं भी है? अथवा यह न तो कण है और न ही कण है?

कुछ समझ हो जाने पर हम चर्चा कर इसका पता लगाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। इस प्रकार हम शिक्षण में दृढ़ विश्वास प्राप्त करते हैं। फिर हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अर्थ पर दिन-रात चिंतन करके हम अपनी समझ का विस्तार करते हैं। यह दृष्टिकोण विशेषकर नालंदा परंपरा से संबंधित है। शांतरक्षित और अन्य भारत-तिब्बती विद्वानों ने जो सीखा था उस पर विचार किया और उसे अपने भीतर संजोया। यह महत्वपूर्ण है कि हम भी ऐसा करें। मुद्दा अध्ययन, चिंतन और साधना करने का है।

हमें शिक्षण में अंतर्निहित कारणों की तलाश करनी चाहिए। हम केवल शास्त्रीय ग्रंथों के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें उनके अर्थ को जीवंत अनुभव में बदलना होगा।

आपमें से जिन लोगों ने आज गेशे की डिग्री ग्रहण की है, उन सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने जो सीखा है उसे व्यवहार में लाकर दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। अध्ययन, चिंतन और मनन के माध्यम से आपने जो सीखा है उसे अपने दिमाग में संजो कर रख सकते हैं।

परसों जापान में जोरदार भूकंप आया। वहां बहुत से लोग अब चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। जापान एक बौद्ध देश है जहां वे 'हृदय सूत्र' का पाठ भी करते हैं। जब भी विश्व में कहीं भी कोई आपदा आती है तो हमें प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। तो आइए आज जापान के लोगों, विशेषकर भूकंप पीड़ितों के लिए मिलकर 'हृदय सूत्र' का पाठ करें।'

इसके बाद परम पावन की सलाह के अनुरूप पूरी सभा 'हृदय सूत्र' का जाप करने के लिए एक साथ आ गई और जाप को सिंह-मुखी डाकिनी के मंत्र के कुछ पाठों के साथ पूरा किया।

## ◆ बारहवें एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन ने परम पावन दलाई लामा को 'बौद्ध धर्म का वैश्विक सर्वोच्च धर्मगुरु' घोषित किया

tibet.net, २३ जनवरी २०२४

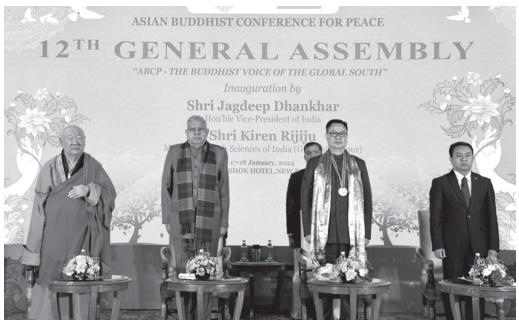


**धर्मशाला।** नई दिल्ली में १७ और १८ जनवरी को आयोजित एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन (एबीसीपी) की १२वीं महासभा ने सर्वसम्मति से परम पावन दलाई लामा को 'बौद्ध धर्म का वैश्विक सर्वोच्च धर्मगुरु' घोषित किया। ऐसा करके बौद्ध समुदायों को करीब लाने और मानवता की एकता की भावना को मजबूत करने में उनके आजीवन योगदान को एक तरह से मान्यता प्रदान की गई।

'द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' थीम वाले दो दिवसीय सम्मेलन में परम पावन १४वें दलाई लामा के जन्मदिन ०६ जुलाई को 'वैश्विक करुणा दिवस' के रूप में घोषित किया गया, जो भगवान बुद्ध और परम पावन की मूल उपदेशों का सम्मान है। इसमें कहा गया है कि १४वें दलाई लामा एक सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करेंगे। सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में गैडेन फोडरंग संस्थान की महत्ता को स्वीकार किया और परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म की मान्यता में सरकारों या व्यक्तियों के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया।

एबीसीपी की १२वीं महासभा के उद्घाटन समारोह के लिए परम पावन दलाई लामा और विभिन्न देशों के प्रमुख नेताओं ने शुभकामना संदेश भेजे। अपने पत्र में परम पावन ने 'एशिया और दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के साथ-साथ बौद्ध संस्कृति और मूल्यों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पहल करने के लिए एबीसीपी की सराहना की।

आज की दुनिया में यह बहुत स्पष्ट है कि दूसरे लोगों को 'हम' और 'वे' के संदर्भ में देखने की हमारी प्रवृत्ति दुर्भाग्य

से मतभेदों को पैदा करती है और संघर्षों को जन्म देती है। पत्र में आगे कहा गया है, 'ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मानवता की एकता की सराहना करने में विफल रहते हैं। हालांकि, जब हम यह जान जाएंगे कि हम सभी एक जैसे इंसान हैं तो हम सद्भाव और दोस्ती में रहना और एक-दूसरे की मदद करना सीख सकते हैं। सम्मेलन को दिया गया परम पावन का संदेश गरीबी और पर्यावरणीय संकट से उत्पन्न खतरों को कम करने को लेकर भी सुझाव देता है। इसमें कहा गया है कि इससे न केवल उन लोगों को मदद मिलेगी जो आज जीवित हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मदद मिलेगी।

इसके अलावा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया। सम्मेलन में भारत, मंगोलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, लाओस, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, भूटान और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

धर्म और संस्कृति विभाग के सचिव चाइम छेयांग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में एबीसीपी के सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधियों द्वारा अपनी रिपोर्ट पढ़ने के बाद एबीसीपी इंडियन नेशनल सेंटर के सचिव सोनम वांगचुक शक्स्पो ने सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को पढ़ा।

## ◆ जापान में भूकंप को लेकर परम पावन का संदेश

dalailama.com, ०२ जनवरी २०२४

**बोधगया, बिहार, भारत।** परम पावन दलाई लामा ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को पत्र लिखकर ०१ जनवरी के भूकंप को लेकर दुख व्यक्त किया है। इस भूकंप से वहां कई लोगों की मौतें हुईं और अनेक लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही संपत्ति और बुनियादी ढांचे का भारी विनाश हुआ है।

उन्होंने लिखा, 'मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उनके परिवारों और इस आपदा से प्रभावित अन्य लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जापानी सरकार जरूरतमंद लोगों को राहत और सहायता पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मैं बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रतिदिन 'हृदय सूत्र' का पाठ करता हूं। मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा यदि जापानी बौद्ध भी इस अवसर पर इस सूत्र का पाठ करें। इस तरह के पाठ से न केवल उन लोगों को फायदा होगा जिनकी मौत हो चुकी हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली आपदाओं को भी रोका जा सकता है।

मैं इस समय भारत के पवित्र स्थान बोधगया में हूं, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। संघ के सदस्यों और वर्तमान में इस पवित्र स्थान की तीर्थयात्रा पर आए अन्य लोगों के साथ हम जापान में इस आपदा के पीड़ितों के लिए 'हृदय सूत्र' का पाठ करेंगे।

परम पावन ने एक बार फिर प्रार्थना करते हुए अपने पत्र का समापन किया।

## ◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को बधाई दी

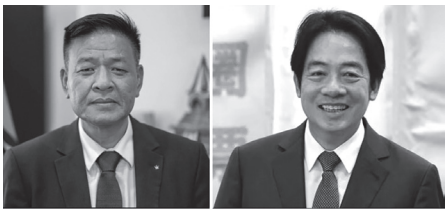

tibet.net, १३ जनवरी, २०२४

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी है।

सिक्योंग ने अपने पत्र में लिखा, 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से मैं आपको और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। आपका चुनाव लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति ताइवान के लोगों की अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

महामहिम छाई इंग-वेन के दूरदर्शी नेतृत्व में ताइवान लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में बहादुरी से सबसे आगे खड़ा रहा है और सभी बाधाओं के बावजूद ताइवान के हित को मजबूत करने में उनके साहस और दूरदर्शिता को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

महामहिम ने हाल ही में बयान दिया था कि ताइवान का भविष्य उसके लोगों को तय करना है। ताइवान की स्थिति ठीक तिब्बतियों की स्थिति के ही समान है। तिब्बती लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान के साथ निर्वासित लोकतंत्र में आत्मनिर्णय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा होने के नाते फलने-फूलने की स्वतंत्रता के मूल्यों को गहराई से संजोते हैं।

सिक्योंग ने ताइवान और तिब्बत के बीच मजबूत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों के साथ-साथ लोकतंत्र और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता की ओर भी इंगित किया।

हमारे ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि के अलावा परम पावन दलाई लामा के प्रति ताइवान के बहुमत की हार्दिक श्रद्धा, लोकतंत्र और लोगों के बीच हमारी साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से तिब्बतियों और ताइवानियों के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं।'

पत्र के अंत में उन्होंने लिखा है, 'तिब्बत और दुनिया भर में तिब्बतियों की ओर से मैं एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपका कार्यकाल सफलता, समृद्धि और उन मूल्यों के प्रति निरंतर समर्पण के लिए विख्यात हो, जिन्हें आप संजोते हैं।'

## ◆ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ७५वां गणतंत्र दिवस मनाया

tibet.net, २६ जनवरी २०२४

**धर्मशाला।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने २६ जनवरी १९५० को भारत में इसका संविधान लागू होने की याद में २६ जनवरी २०२४ को गंगचेन किइशोंग में भारत का ७५वां गणतंत्र दिवस मनाया।

समारोह में निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल, शिक्षा विभाग के कार्यवाहक सिक्योंग कालोन (मंत्री) थारलम डोल्मा चांगरा, निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग, न्याय आयुक्त तेनज़िन लुंगटोक, कालोन नोरज़िन डोल्मा के अतिरिक्त सीटीए के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ध्वजारोहण के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सिक्योंग कालोन थरलाम डोल्मा चांगरा ने इस अवसर पर तिब्बती लोगों की ओर से भारत सरकार और लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 'भारत इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक लोकतांत्रिक प्रणाली सुचारू रूप से फल-फूल रही है और यह बाकी दुनिया के लिए एक सबक है जिसका उन्हें अनुकरण करना चाहिए, जैसा कि हमने किया है। उन्होंने कहा कि निर्वासन में भारत आने के तुरंत बाद परम पावन दलाई लामा ने सरकार का एक लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया जो तिब्बत के इतिहास में कभी अस्तित्व में नहीं था। हम भारत के नक्शेकदम पर चले हैं। भारत सरकार और यहां के लोग निर्वासित तिब्बतियों के प्रति बहुत दयालु रहे हैं और तिब्बतियों के लिए उनका ऐसा होना काफी महत्वपूर्ण है।' इस संबंध में उन्होंने भारत की आजादी के बाद की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया और इसकी संपन्न लोकतांत्रिक प्रणाली की सराहना की।

इसी तरह निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोलमा छेरिंग तेखांग ने भी मीडिया को संबोधित किया और कहा, 'इस अवसर पर मैं प्रगतिशील भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूं।'

## ◆ सिक्योंग पेन्पा ने एस्टोनियाई संसद में 'तिब्बत की वैधानिक स्थिति' पर सुनवाई में भाग लिया

tibet.net, २६ जनवरी, २०२४

**एस्टोनिया।** तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण उस समय आया जब, २५ जनवरी २०२४ को एस्टोनियाई संसद में 'तिब्बत की वैधानिक स्थिति' को लेकर सुनवाई हुई। इसकी अध्यक्षता पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत के अध्यक्ष और विदेश मंत्रालय संबंधित आयोग का सदस्य सांसद जुकू-काले रेड ने की। सिक्योंग पेन्पा छेरिंग को सुनने के लिए ३५ सांसद, पत्रकार, शिक्षाविद, लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय से प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी, प्रोफेसर होन-शियांग लाउ, डॉ. माइकल वान वॉल्ट वान प्राग और तिब्बत समर्थक उपस्थित थे।

अध्यक्ष सांसद जुकु-काले रेड ने तिब्बत मुद्दे की पृष्ठभूमि और घटना के महत्व के बारे में बताते हुए सुनवाई शुरू की। सुनवाई में सबसे पहले माननीय सिक्योंग का बयान हुआ। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा आक्रमण से पहले स्वतंत्र तिब्बत की पूरी कहानी, मध्यम-मार्ग दृष्टिकोण और तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्यों को सही करने के महत्व को ऐतिहासिक संदर्भ देकर समझाया।

इसके बाद प्रोफेसर लाउ ने चीनी शाही अभिलेखों से लेकर प्रमाण दिया, जिससे बिना किसी संदेह के साबित होता है कि चीनी मिंग और किंग राजवंशों ने कभी भी तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में दर्ज नहीं किया। ये चीनी राजवंश के रिकॉर्ड से निर्विवाद और सच्चाई से यह साबित करते हैं कि तिब्बत प्राचीन काल से कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। डॉ. माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग ने अपनी प्रस्तुति में इस तथ्य को कानूनी दृष्टिकोण से और भी मजबूत किया। इसमें बताया गया कि चीन तिब्बत पर अपने कब्जे की वैधता क्यों चाहता है। चीन द्वारा तिब्बती लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करने का औचित्य ठहराने के लिए अपने व्यापारिक साझेदार सरकारों पर 'तिब्बत को चीन का आंतरिक मुद्दा' घोषित करने का दवाब डाला जा रहा है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली है।

इसके बाद प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी ने तिब्बत के ऐतिहासिक और पौराणिक अभिलेखों का हवाला देकर चर्चा को सही दिशा में स्थापित किया। उन्होंने तिब्बत की उत्पत्ति, तिब्बती लोगों और दुनिया में शांति लाने के लिए दलाई लामाओं के बीच पूर्व-नियत संबंधों की व्याख्या के बारे में बात की। उन्होंने तिब्बत में पीआरसी शासन की कठोर उपनिवेशवादी प्रकृति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि तिब्बत में शांति बहाल करने के लिए तिब्बती मुक्ति साधना का शांतिपूर्ण और अहिंसक समाधान तैयार करना जरूरी है। इससे शांति और अहिंसक उपायों के प्रति वैश्विक विश्वास बढ़ेगा जिससे दुनिया के कुछ हिस्से में हिंसा के दुष्चक्र को समाप्त करने में कारगर साबित होगा।

स्वतंत्र एस्टोनिया के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री माननीय मार्ट लार ने सुनवाई

के समर्थन में अपना संदेश भेजा, जिसका वाचन एस्टोनियाई में सांसद जुकु-काले रेड द्वारा और अंग्रेजी में लंबे समय से कट्टर तिब्बत समर्थक रॉय स्ट्राइडर द्वारा किया गया। सुनवाई के बाद संसद में स्वागत समारोह आयोजित किया गया जहां वक्ताओं और दर्शकों को बातचीत के लिए अधिक समय मिला। पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों और स्थानीय समर्थकों ने इस समारोह में आए तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया।

माननीय सिक्योंग का २५ जनवरी को हवाई अड्डे पर सांसद जुकु-काले रेड ने स्वागत किया, जिन्होंने आज २६ जनवरी को एस्टोनियाई संसद का व्यक्तिगत दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने रिइगीकोगु के राष्ट्रपति लॉरी हुसार के साथ-साथ विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। दो मीडिया संस्थानों के संवाददाता सिक्योंग की संसद यात्रा में साथ रहे और रिपोर्ट की। परिणामस्वरूप, एस्टोनियाई मीडिया ने कल इस कार्यक्रम का जोर शोर से कवरेज दिया।

## ◆ तिब्बती छात्रों को बाहर से पढ़ाई करने पर प्रतिबंध अपराधियों को ढूंढने के लिए रात-दिन जांच की जा रही है।

rfa.org, ०९ जनवरी २०२४

तिब्बत के अंदर से रेडियो फ्री एशिया के तीन सूत्रों ने उसे बताया कि चीनी अधिकारी तिब्बत में घर-घर जाकर तिब्बती बच्चों को शीतकालीन अवकाश के दौरान निजी क्लास करने और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

सूत्रों ने कहा कि अधिकारी 'आवासीय क्षेत्रों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' में औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

अधिकारियों ने २०२१ में तिब्बती आबादी वाले विभिन्न प्रांतों में तिब्बती बच्चों को जाड़े की छुट्टियों में तिब्बती भाषा की अनौपचारिक कक्षाओं या कार्यशालाओं में पढ़ने से रोकना शुरू किया। यह एक ऐसा कदम था, जिसके बारे में स्थानीय तिब्बतियों और प्रभावित बच्चों के माता-पिता ने कहा कि इससे बच्चों का उनकी मूल भाषा से जुड़ाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सूत्रों ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस साल जनवरी की शुरुआत में चीनी शिक्षा विभाग ने इस प्रतिबंध को दोहराते हुए एक नोटिस जारी किया। नोटिस में स्थानीय अधिकारियों को तिब्बती बच्चों की अतिरिक्त पढ़ाई की निगरानी और जांच तेज करने और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

स्थानीय अधिकारियों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आवासीय क्षेत्रों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिन और रात के स्तर पर लगातार जांच की जानी चाहिए।

इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के सूत्रों ने आरएफए को बताया कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थानीय अधिकारियों, गांसु प्रांत में लाब्रांग मठ और किंघई प्रांत में युशू तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर ने शिक्षा विभाग के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

ल्हासा शहर के अधिकारियों ने ३० नवंबर, २०२३ को एक नोटिस जारी किया, जिसमें ३० दिसंबर से २७-२९ फरवरी, २०२४ तक सभी तीन स्तरों के स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई। नोटिस में विस्तार से बताया गया कि माता-पिता अवकाश के दौरान अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही बताया गया कि शिक्षकों को अवकाश अवधि के दौरान क्या-क्या कार्य करने की आवश्यकता होगी।

***कोई धार्मिक शिक्षा नहीं :***

सूत्रों से आरएफए को प्राप्त नोटिस में कहा गया है कि अभिभावकों को बच्चों के स्कूलों की धार्मिक शिक्षा में खुद भी शामिल नहीं होना चाहिए और यह 'सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे धर्म के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहें।'

नोटिस में कहा गया है कि तिब्बती अभिभावकों को अपने बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे 'स्वेच्छा से पूजा स्थलों से दूरी बनाए रखें और वे किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा न करें।'

दक्षिण-पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में युशू तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर के सूत्र ने कहा, 'स्थानीय अधिकारी घर-घर जाकर जांच के अलावा तिब्बती बच्चों का सर्वेक्षण भी कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें स्कूल से बाहर के पाठ्यक्रमों में कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं और कहां पढ़ाए जा रहे हैं।'

सूत्रों ने कहा कि शिक्षा विभाग के नोटिस में कहा गया है कि तिब्बती बच्चे केवल सरकार द्वारा अधिकृत शिक्षकों और संगठनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले और अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विषयों पर ही पूरक कक्षाओं और कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नोटिस में तिब्बती बच्चों की धार्मिक गतिविधियों में

भागीदारी पर जारी प्रतिबंध पर जोर देने वाले आदेश भी हैं।

ज़ियाहे काउंटी स्थित लैब्रांग मठ के एक सूत्र ने कहा, 'अतीत में यहां तिब्बती बच्चों को शीतकालीन अवकाश के दौरान तिब्बती व्याकरण, धर्म, गणित और कहानी कहने के क्षेत्र में पूरक, निजी ट्यूशन प्रदान करने की मजबूत परंपरा थी। - लैब्रांग मठ तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के बाहर सर्वाधिक भिक्षुओं की आबादी वाला केंद्र है।'

'तिब्बती छात्रों को अब राजनीतिक पुन: शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले केवल वही गिने-चुने संगठन और व्यक्ति पढ़ा सकते हैं, जिन्हें चीनी सरकार ने अधिकृत किया हैं।'

उसी स्रोत ने तिब्बती भाषा के अध्ययन और तिब्बती बच्चों के धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किए जाने की भी पुष्टि की है। सर्वविदित है कि चीन तिब्बती भाषा और तिब्बत के धर्म पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 'धर्म का चीनीकरण' अथवा 'धर्म को चीन के समाजवादी समाज के अनुकूल बनाने।' की योजनाओं को थोपने के प्रयासों को तेज कर रहा है।

एक अन्य सूत्र ने आरएफए को बताया कि स्कूलों और स्कूल के बाहर के कार्यक्रमों में तिब्बती भाषा के अध्ययन पर प्रतिबंध के कारण स्पष्ट है कि युवाओं और तिब्बती बच्चों का अपनी मूल भाषा और पहचान से संपर्क टूट गया है। यह बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक प्रवृत्ति है।'

***कक्षाओं में केवल चीनी भाषा :***

रेडियो फ्री एशिया ने मार्च २०२२ में बताया कि चीनी अधिकारी स्कूलों में तिब्बती भाषा की शिक्षा को हटाकर चीनी करने की नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सभी कक्षाएं केवल चीनी भाषा में पढ़ाई जाएंगी। आलोचकों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य तिब्बती बच्चों का उनकी राष्ट्रीय पहचान और पारंपरिक भाषा और संस्कृति के साथ उनके संबंधों को कमजोर करना है।

एक साल पहले न्यू मैक्सिको स्थित सांता फ़े नामक तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ०४ से १८ वर्ष की उम्र के बीच के लाखों तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया जा रहा है और उन्हें सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में जबरन भर्ती किया जा रहा है। वहां शिक्षक केवल मंदारिन में बोलते हैं और नर्सरी में बाल-कविताओं से लेकर सोते समय तक मंदारिन में ही कहानियां और लोरियां सुनाई जाती हैं। इसके बीच दिन भर में पढ़ाए जाने वाले सभी स्कूली पाठ्यक्रम भी मंदारिन में ही होते हैं।'

अधिकार कार्यकर्ताओं ने तिब्बती बच्चों को पूरी तरह से चीनी बहुमत वाली आबादी में विलीन कर देने के इस कदम की निंदा की है और दीर्घकाल में तिब्बती पहचान के अस्तित्व पर पड़नेवाले इसके संभावित दुष्प्रभावों की आशंका जताई है।

सितंबर २०२३ की आरएफए जांच रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कब्जे वाले तिब्बत में लौटने वाले प्रवासी तिब्बतियों ने इस बात कि पुष्टि की कि वे बोर्डिंग स्कूलों में जाने वाले अपने युवा रिश्तेदारों में इस कदम के दुष्प्रभाव को देख रहे हैं। वहां की पूरी पढ़ाई केवल मंदारिन में होती है और वे आपस में भी इसी भाषा में बात करते हैं।

## ◆ तिब्बत के बौद्ध मठों में किसी नए भिक्षु के प्रवेश की अनुमति नहीं सूत्रों का कहना है कि यह कदम धार्मिक गतिविधियों पर चीन के कठोर नियंत्रण को दर्शाता है।

rfa.org, ०३ जनवरी २०२४

चीनी अधिकारियों द्वारा देश में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों को कड़ा किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया से परिचित दो सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया को यह जानकारी दी है। इसके साथ ही पूर्वी तिब्बत के चामदो प्रिफेक्चर के एक तिब्बती बौद्ध मठ में सभी उम्र के नए भिक्षुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

क्षेत्र के अंदर से एक सूत्र ने बताया कि यह पहली बार है कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के मठवासी जीवन में शामिल होने के लिए नामांकन कराने से सभी उम्र के भिक्षुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह का प्रतिबंध हालांकि पहले भी था लेकिन पहले केवल नाबालिगों या १८ वर्ष से कम उम्र के नौजवानों को ही इसमें शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था।

सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करते हुए सूत्र ने कहा, 'अब अधिकारियों ने मार्खम (काउंटी) में ख्युंगबम लूरा मठ में भी किसी नए भिक्षुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।'

सूत्रों ने आरएफए को बताया कि ख्युंगबम लूरा मठ काउंटी में तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या येलो हैट संप्रदाय के सबसे बड़े मठों में से एक है जो ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के खाम क्षेत्र का एक हिस्सा है। वर्तमान में इस मठ में ८० से अधिक भिक्षु हैं।

माना जाता है कि मठ के भिक्षुओं ने १९५० में तिब्बत के चामडो पर आक्रमण करने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का विरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों ने छह साल से अधिक समय में केवल एक स्तूप को छोड़कर मठ के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था।

इसके बाद १९८० के दशक की शुरुआत में तिब्बत में शुरू किए गए तथाकथित उदारीकरण कार्यक्रम के बाद स्थानीय तिब्बतियों और शेष भिक्षुओं ने मठ के कुछ हिस्सों को पुनर्स्थापित करने के लिए काम शुरू किया।

चीनी अधिकारियों ने 'धार्मिक मामलों के नियमन' नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। यह दस्तावेज नेशनल रिलिजियस अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन (राष्ट्रीय धार्मिक मामलों के प्रशासन) द्वारा धार्मिक गतिविधियों, वहां के कर्मियों और स्थलों पर नियमों को निर्धारित करता है। यह कम्युनिस्ट पार्टी की एजेंसी- यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की एक शाखा है जो विदेशों में चीन के धार्मिक, जातीय मामलों में विदेशी अभियानों की देख-रेख करती है।

विनियमन में कहा गया है कि स्कूलों या शैक्षणिक निकायों में कोई भी धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जा सकती हैं और १८ वर्ष से कम आयु के तिब्बतियों को मठों में नामांकन करने से कठोरता से प्रतिबंधित किया जाता है।

*स्थानीय प्रशासक*

दो सूत्रों ने कहा कि धार्मिक गतिविधियों पर चीन की कड़ी निगरानी का एक प्रमाण यह है कि अधिकारियों ने ख्युंगबम लूरा मठ के संचालन की निगरानी के लिए एक स्थानीय प्रशासक नियुक्त कर दिया है। साथ ही धमकी दी है कि अगर नियमों का पालन करने में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर इस मठ को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल, ख्युंगबम लूरा मठ पारंपरिक रूप से वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा चलाया जाता है।

सूत्रों ने कहा कि मार्खम काउंटी के निवासी तिब्बती ख्युंगबम लूरा मठ में किसी भी नए भिक्षु के प्रवेश पर रोक लगाने वाले नए नियम के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।

क्षेत्र के अंदर के सूत्रों ने कहा कि नए भिक्षुओं के नियमित प्रवेश न होने से अंततः मठ का पतन हो जाएगा और भविष्य में मठ बंद हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय तिब्बतियों के पास महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों के लिए कोई पूजास्थल नहीं रह जाएगा और उपासना-प्रार्थना, विशेष रूप से परिजनों की मृत्यु पर अनुष्ठान करने के लिए यहां कोई भी नहीं आएगा।

चीनी अधिकारी लंबे समय से तिब्बती बौद्ध मठों के स्वरूप और प्रभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से तिब्बती सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के केंद्र हैं।

हाल ही में जनवरी २०२१ में नेशनल रिलिजियस अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन (राष्ट्रीय धार्मिक मामलों के प्रशासन) द्वारा पारित किए गए कम्युनिस्ट पार्टी के 'पुजारियों के लिए प्रशासनिक उपाय' संबंधी विनियमन दस्तावेज के अनुसार, धार्मिक पुरोहितों के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 'धर्म के चीनीकरण' या 'चीन के समाजवादी समाज के अनुरूप धर्म विलयीकरण' योजना का समर्थन करना और देश के राष्ट्रीय हित और विचारधारा के अनुसार काम करना आवश्यक है।

चीनी अधिकारियों ने जुलाई २०१८ में तिब्बत के ऐतिहासिक खाम के पूर्वी क्षेत्र के डज़ाचुका में जोवो गैंडेन शेड्रब पालग्येलिंग मठ से १५ वर्ष से कम उम्र के युवा भिक्षुओं को निकाल दिया है। यह कदम चीन की स्टेट काउंसिल द्वारा नवंबर २०१७ में 'धार्मिक मामलों पर विनियमों' का अद्यतन संस्करण जारी करने के तुरंत बाद उठाया गया।

इसके बाद से तिब्बती-आबादी वाले विभिन्न प्रांतों में ११ से १५ वर्ष की आयु के युवा तिब्बती भिक्षुओं को चीवर त्यागने और मठों को छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने की कई रिपोर्टें आई हैं। इनमें धित्सा, जख्युंग और किंघई प्रांत के अन्य मठ शामिल हैं।

## ◆ सिक्योंग ने तिब्बत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लैटिवियन पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों से मुलाकात की

tibet.net, ३० जनवरी २०२४

रीगा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के माननीय सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २९ जनवरी २०२४ को सुबह ही लातविया के सरकारी रेडियो और एक अन्य मीडिया संस्थान को रीगा (लातविया) में साक्षात्कार दिया और यहां अपने दिन की शुरुआत की।

दोपहर में, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने लैटिवियन पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत (तिब्बत के लिए लातिवियाई संसदीय समर्थक समूह) के सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग लिया। यहां उन्होंने तिब्बत की वर्तमान स्थिति, यूक्रेन और तिब्बत की परिस्थितियों के बीच समानताएं, तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और लातवियाई संसद द्वारा संभावित ठोस कार्रवाई के विचारों पर चर्चा की। उन्होंने तिब्बत मुद्दों पर समर्थन देने के लिए लातवियाई संसद सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर २०२२ में तिब्बत पर विश्व सांसद सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग भी उपस्थित थे। इसके साथ ही माननीय सिक्योंग ने पिछले सप्ताह चीन पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आवधिक समीक्षा के दौरान चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लातवियाई सरकार की ओर से कोई बयान न आने पर निराशा भी व्यक्त की।

बाद में शाम को उप महापौर लिंडा ओज़ोला द्वारा रीगा सिटी काउंसिल में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। यहां 'तिब्बतन वॉरियर (तिब्बती योद्धा)' फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र और फिल्म स्क्रीनिंग में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दर्शकों में से कई लोगों ने रूस से स्वतंत्रता के अपने देश के अनुभव सुनाए और तिब्बती मुद्दे के प्रति सहानुभूति, समर्थन और आशा की उम्मीदों का इजहार किया।

## ◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने लिथुआनियाई संसद में ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहे तिब्बत की वकालत की

tibet.net, ३१ जनवरी, २०२४

**विल्नियस।** लातविया में सरकारी और गैर-सरकारी समूहों के बीच सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखने के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल कल ३० जनवरी को लिथुआनिया के विल्नियस पहुंचा। लिथुआनियाई तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष विटिस विल्डुनास ने हवाई अड्डे पर तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

बाल्टिक देशों और फ़िनलैंड की अपनी पहली यात्रा के दौरान सिक्योंग पेन्पा छेरिंग

ने इन देशों में सरकार, राजनेताओं और नागरिक समाज को साक्ष्य-आधारित प्रकाशित स्रोतों के बारे में जानकारी दी (तिब्बत ब्रीफ २०/२०, प्राचीन काल से तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है, यह छिपा हुआ एजेंडा है)। यह तिब्बत की ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र स्थिति को साबित करता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल के तहत कम्युनिस्ट चीनी सरकार यूरोप के लिए दीर्घकालिक खतरे की घंटी है। हालांकि रूस पर चीन का खतरा तत्काल मंडरा रहा है।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने तिब्बत के लिए समर्थन की अपील और तिब्बत-चीन संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थों के बारे में जागरूक करते हुए यूक्रेन के लिए बाल्टिक लोगों की सार्वजनिक और उचित सहानुभूति के बीच विरोधाभासों को रेखांकित किया। असल में, इन देशों के व्यापारिक संबंध और व्यापार सौदे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की आक्रामकता को मजबूत करते हैं। यूक्रेन पर बाल्टिक देशों के व्यापार घाटे (निर्यात मूल्य पर अतिरिक्त आयात) से चीन को लाभ होता है क्योंकि इससे चीन को विदेशी मुद्रा मिलता है जिसका उपयोग पीआरसी द्वारा रूस से गैस और अन्य सामान खरीदने के लिए किया जाता है। इस तरह से रूसी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह से रूस (अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध से आर्थिक नुकसान को दरकिनार कर देता है) और इस तरह रूस को यूक्रेन पर अपनी आक्रामकता जारी रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता रहता है।

माननीय सिक्योंग ने कम्युनिस्ट यूएसएसआर के शासन के प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद लातवियाई सांसदों द्वारा चीन सरकार द्वारा प्रायोजित चीन की हालिया मुफ्त अनौपचारिक निजी यात्रा के खोखलेपन और भोलेपन का भी विश्लेषण किया। ऐसी मुफ्त यात्राएं चीन में समाजवादी स्वर्ग की कहानिया गढ़ने में सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने दावा किया कि पीआरसी-नियंत्रित क्षेत्रों में 'शासक और शासित' के बीच की असली अग्निपरीक्षा तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान की स्वतंत्र, निगरानी से मुक्त खुली यात्राओं की अनुमति देने से हो जाएगी। इसमें ध्यान देने की बात है कि चीन द्वारा मित्र देशों के लिए केवल वीज़ा-मुक्त १५-दिवसीय यात्रा की बात नहीं होनी चाहिए। सिक्योंग की स्पष्ट चर्चाओं और तीखी टिप्पणियों की कई लोगों ने सराहना की। सिक्योंग ने यहां कोविड महामारी, यूक्रेन-रूस युद्ध, ऋण कूटनीति के बाद चीन की प्रेरणाओं के प्रति 'असभ्य जागृति' की बात की। लोगों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किसी भी आह्वान के प्रति पीआरसी के अधिकारियों के असम्मानजनक आक्रामक रवैये और लोकतांत्रिक देशों में कानून के शासन और मिलने की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होने के बारे में भी बात की। मिलने की यह स्वतंत्रता किसी के साथ नहीं है, चाहे वह तिब्बती हों, उग्यूर, ताइवानी, हांगकांगवासी, दक्षिणी मंगोलियाई या मंचूरियन हों।

बैठकों के अलावा विल्नियस के एजेंडे में विल्नियस के तिब्बत स्क्वायर की यात्रा भी शामिल है। तिब्बत स्क्वायर तिब्बत से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों, जैसे- तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति, परम पावन १४वें दलाई लामा के जन्मदिन आदि के स्मरणोत्सव के लिए एक मील का पत्थर बन गया है।

## ◆ २०२३ में तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति, एक वर्ष की समीक्षा

tibet.net, १३ जनवरी, २०२४

धर्मशाला। वर्ष २०२३ वैश्विक संघर्षों के मामले में महत्वपूर्ण रहा क्योकि इस वर्ष कई नए संघर्षों का जन्म हुआ। इसमें दो प्रमुख युद्ध और कई अन्य लोगों की मौतें शामिल हैं। हालांकि, दुनिया आज के इन संकटों और संघर्षों से निपट रही है, लेकिन तिब्बत तो पिछले छह दशकों से अधिक समय से एक ऐसा स्थान रहा है, जहां पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की सरकार द्वारा कुछ सबसे अधिक दिखाई देने वाले और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन हुए हैं। यहां मानवाधिकारों की स्थिति २०२३ में अलग नहीं रही है।

फ्रीडम हाउस ने लगातार तीसरे वर्ष १०० में से केवल एक स्कोर देकर तिब्बत को पृथ्वी पर सबसे कम मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थान दिया है। २०२३ में चीन लगातार नौवें वर्ष मुक्त अभिव्यक्ति के रूप में इंटरनेट स्वतंत्रता को बाधित करने वाला दुनिया का सबसे संगीन अपराधी बना रहा। देश में नागरिकों की सूचना तक पहुंच, सोशल मीडिया की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाए जाने और प्रमुख अधिकार कार्यकर्ताओं और ब्लॉगर्स को लंबी कारावास की सजा देने के साथ चीन का तिब्बत में दमन जारी है।

तिब्बत में पीआरसी सरकार का 'चीनीकरण' अभियान लगातार तेज़ हो रहा है, जो लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को सरकार द्वारा संचालित औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती करने से स्पष्ट है। यहां तक कि पूरे क्षेत्र में तिब्बती स्कूलों को सुनियोजित तरीके से बंद किया जा रहा है। सरकारी अखबारों में बोर्डिंग स्कूलों का प्रचार बेतहाशा हो रहा है। इससे पता चलता है कि चीन सरकार तिब्बत के सभी क्षेत्रों के बच्चों को इसी तरह की शिक्षा देने का इरादा रखती है। हालांकि, वे पाठ्यक्रम संबंधी गंभीर चिंताओं या भेदभावपूर्ण नीतियों को ठीक करने में विफल रहे जो तिब्बती छात्रों के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा शिक्षा की राह में बाधा डालती हैं। केवल पिछले साल ३४ हजार से अधिक तिब्बती निवासियों को विभिन्न कारणों से अपनी पारंपरिक भूमि से सरकार द्वारा निर्मित आवास में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें जलविद्युत परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाना, तथाकथित पारिस्थितिक संरक्षण और तिब्बतियों को एक निश्चित बस्तियों में बसाकर उन पर पीआरसी सरकार के नियंत्रण को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

निर्वासित तिब्बतियों के मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कम से कम ४० तिब्बती भिक्षुओं और आम जन को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। इनमें से आठ को अपनी तिब्बती पहचान को अभिव्यक्त करने के आरोप में तीन साल तक की जेल की सजा मिली है। यातना को मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माने जाने के बावजूद चीनी जेलों पर इसका कोई असर नहीं है और वहां यातना देना आम बात है। कई रिपोर्टें सामने आई हैं कि तिब्बती राजनीतिक कैदियों की चीनी हिरासत में मौत हो गई है, कैदियों को बहुत खराब स्वास्थ्य के कारण या मेडिकल पैरोल पर रिहा कर दिया गया है और तिब्बती कार्यकर्ताओं को

चीनी अधिकारियों या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों द्वारा पीटा गया है। तिब्बती अधिकार कार्यकर्ता गोंपो की पर चीनी अधिकारियों द्वारा बार-बार किए गए हमले दर्शाते हैं कि चीनी सरकार किस हद तक तिब्बतियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि इस बारे में चीनी कानून में गारंटी है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अपील करने का अधिकार भी शामिल है। तिब्बती भाषा अधिकार कार्यकर्ता ताशी वांगचुक पर भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने एक होटल के कमरे में घात लगाकर हमला किया और बाद में स्थानीय नगरपालिका ने उन्हें व्यापार लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। यह पूर्व राजनीतिक कैदियों पर लगातार हमलों और उनके साथ दुर्व्यवहार का स्पष्ट उदाहरण है। केवल तिब्बती पहचान को अभिव्यक्त करने और तिब्बती भाषा के उन्मूलन के बारे में चिंता व्यक्त करने मात्र से ही ज़ंगकर जामयांग और गोलॉग पाल्डेन की लंबी जेल की सज़ाएं और प्रभावशाली तिब्बती हस्तियों पर हमला पीआरसी सरकार की लापरवाही और चीनी उत्पीड़न को दर्शाती है। चार तिब्बतियों को अपने गांव में धार्मिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए दो-दो साल की कैद की सजा दी गई। इस कार्यक्रम में केवल सांग-सोल, आध्यात्मिक प्रदूषण या रुकावटों की शुद्धि या शुद्धीकरण और तिब्बती बौद्ध धार्मिक लोगों की दीर्घायु और भलाई के लिए प्रार्थना किया जाना था। इसके अलावा, छुल्ट्रिम नाम के एक तिब्बती पुरुष और सेमकी डोल्मा नाम की एक तिब्बती महिला को परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें रखने और निर्वासित तिब्बतियों के साथ संवाद करने के दोष में क्रमशः ढाई और डेढ़ साल की कैद की सजा सुनाई गई। कुख्यात 'धार्मिक गतिविधि स्थलों के प्रशासन के लिए उपाय' या आदेश-१९ को लागू करके पीआरसी सरकार ने 'धर्म के चीनीकरण' करने को अपने राष्ट्रीय कानूनों का अनिवार्य हिस्सा बनाया है। ऐसा करके सरकार ने धार्मिक संस्थानों को अपने अधीन करने और उन पर नियंत्रण हासिल करने के अपने दुर्भावनापूर्ण प्रयासों का प्रदर्शन किया है। अन्य बातों के अलावा यह अनिवार्य है कि धार्मिक संस्थान अपने सदस्यों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करें, जहां सदस्यों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों और दिशा-निर्देशों, कानूनों और विनियमों और चीन की 'उत्कृष्ट पारंपरिक संस्कृति' और धर्म के बारे में निर्देश दिया जाएगा। तिब्बती लोगों को अपनी धार्मिक पहचान को अभिव्यक्त करने और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर कठोर दंड और मनमानी हिरासत का सामना करना पड़ रहा है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को कालचक्र के एक प्रमुख बौद्ध कार्यक्रम में भाग लेने से इस डर से रोक दिया है कि १,००,००० से अधिक लोगों की सभा सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इस सबसे दो बुनियादी तथ्य निकाले जा सकते हैं, पहला तिब्बती लोगों में सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अभाव है और दूसरा चीनी सरकार तिब्बत पर शासन को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है।

तिब्बतियों की निगरानी और उनको नियंत्रित करने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों का उपयोग, दुष्प्रचार अभियान और सेंसरशिप जैसी निगरानी रणनीतियों से तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ०१ फरवरी २०२३ से लागू 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) साइबर सुरक्षा प्रबंधन विनियम' में तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को सख्त नियमों और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। कानून यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किन उल्लंघनों के कारण किसी तिब्बती को अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी पुलिस को तिब्बतियों को सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक बातचीत के लिए निशाना बनाने की मनमानी शक्ति मिल जाती है। नियमों ने तिब्बतियों के जीवन में व्यवधान और असफलताएं पैदा की हैं। इस तरह वे अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन करने और अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए कई तिब्बती पुरुषों और महिलाओं को परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें रखने, तिब्बती बौद्ध धर्म पर ऑडियो सुनने, वीचैट जैसे सोशल मीडिया समूहों पर धार्मिक तत्वों को जमा करने या बात करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा सकता है।

पीआरसी सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं के दमन के कारण निर्वासित तिब्बतियों में स्वघोषित सेंसरशिप पैदा हो गई है और वे निरंतर भय में रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप तिब्बत के अंदर रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को पीआरसी सरकार के आशंकित प्रतिशोध से बचाने के लिए उनके साथ संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछले साल, विश्वसनीय रिपोर्टों से पता चला कि जिन तिब्बती युवाओं के परिजन निर्वासित समुदायों में हैं या जो तिब्बत में पीआरसी के दमन को उजागर करने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। इसके कारण उन्हें निर्वासन में अपने परिवारों के साथ संबंध तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चीन का दुष्प्रचार अभियान रणनीतिक रूप से दो लक्ष्यों को साधने के लिए तैयार किया गया है। तिब्बती ऐतिहासिक तथ्यों का मुकाबला करना और अपने मानवाधिकारों के हनन से दुनिया का ध्यान हटाकर उन्हें गुमराह करना। तिब्बत पर 'नए युग में ज़िज़ांग के शासन पर सीसीपी नीतियां: दृष्टिकोण और उपलब्धियां' शीर्षक से जारी नवीनतम 'श्वेत पत्र' का उद्देश्य मुख्य रूप से उन आंकड़ों का उपयोग करके तिब्बत की एक चमकदार छवि चित्रित करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गलत जानकारी देना है जो कि विकास का संकेत देते हैं। जबकि असल में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तिब्बतियों को किसी भी तरह से लाभ नहीं होने दिया जा रहा है। सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में तिब्बत को बदल कर ज़िज़ांग (तिब्बत के लिए चीनी शब्द) कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पीआरसी सरकार तिब्बत पर अपने अवैध कब्जे की वैधता साबित करना चाहती है और एक मूल्यवान संस्कृति को खत्म करके अन्यायपूर्ण तरीके से तिब्बत को पुनः वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है।

सीसीपी दमन के तहत तिब्बत की सभी अन्यायपूर्ण कथानकों के अलावा पिछले साल कानून और प्रस्तावों के पारित होने के साथ-साथ पीआरसी

सरकार की दमनकारी नीतियों की निंदा करने वाले बयानों और रिपोर्टों की भी बाढ़ आ गई है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में तिब्बत के लिए समर्थन बढ़ा है। तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह वकालत के लिए एक मंच प्रदान करता है, राजनयिक दबाव बढ़ाता है और सामान्य रूप से अनिवार्य औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों और 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' कार्यक्रमों सहित अन्य माध्यमों से तिब्बती पहचान को मूल रूप से मिटाने जैसे तिब्बती मुद्दों की समझ को और बढ़ावा देता है।

इसी तरह, पिछले साल बताया गया था कि तिब्बती पहचान में घुसपैठ कर इसे चीनी में बदलने के लिए पीआरसी सरकार के बढ़ते दबाव और दमन के बावजूद तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग तिब्बती पहचान को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## ◆ संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन की समीक्षा में सदस्य देशों द्वारा तिब्बती अधिकारों को अभूतपूर्व समर्थन, बीजिंग ने आलोचना पर चुप्पी साधी

tibet.net, २४ जनवरी, २०२४

जिनेवा। इस साल २३ जनवरी को संयुक्त राष्ट्र के २४ सदस्य देशों ने चीन के चौथे वैश्विक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) चक्र के दौरान अपने मौखिक बयानों में तिब्बत और तिब्बतियों का उल्लेख किया। इनमें से २१ देशों ने तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई, जिसके परिणामस्वरूप २३ सिफारिशें की गईं।

चीन का मानवाधिकार रिकॉर्ड तिब्बतियों, उग्यूरों और हांगकांग में असंतुष्टों के साथ उसके व्यवहार पर गहन जांच का प्रमुख केंद्र था। चीन की समीक्षा में तिब्बत का मुद्दा उठाने वाले देश- ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका थे।

तिब्बत में चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों को सदस्य देशों ने अपने बयानों से व्यापक फलक पर पेश किया। इसमें बीजिंग द्वारा सांस्कृतिक संहार और राजनीतिक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके अधिकारों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। समीक्षा के दौरान मुख्य फोकस विशेष रूप से चीन द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के दमन पर था। सदस्य देशों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की और विशेष रूप से औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों को समाप्त करने का आह्वान किया। इन स्कूलों के माध्यम से १० साल से अधिक तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों, भाषा, धर्म और संस्कृति से अलग कर दिया गया है। सदस्य देशों ने निजी स्कूलों को अधिकृत करने, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए तिब्बतियों की रिहाई और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को तिब्बत में निर्बाध आवागमन की आजादी देने का भी आह्वान किया।

हमेशा की तरह चीन सरकार ने तिब्बत में आवासीय स्कूलों को देश में शिक्षा में समानता लाने के लिए शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर को पाटने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि चीन यह सबूत देने में विफल रहा है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम युवा तिब्बती छात्रों के बीच तिब्बती भाषा या संस्कृति को कमजोर नहीं करता है। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न आंकड़ों के आधार पर कहा कि तिब्बतियों को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि उनके दावे में कोई दम नहीं दिखा। चीनी प्रतिनिधिमंडल द्वारा तिब्बतियों की सहमति से संचालित होने वाली पुनर्वास नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई थी। चीनी राजदूत ने आलोचना का खंडन किया और आरोपों को चीन को कलंकित करने वाला, झूठा और अपमानजनक बताया।

सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग ने संयुक्त राष्ट्र की चीन समीक्षा में तिब्बत का मुद्दा उठाने वाले देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना की और कहा, 'हम उन सभी देशों के आभारी हैं, जिन्होंने पीआरसी सरकार की गैरकानूनी शासन के तहत तिब्बत की गंभीर मानवाधिकार स्थिति को उठाया। तिब्बत के भीतर की स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चीन को वैश्विक आवधिक समीक्षा पर ध्यान देना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों का पालन करना चाहिए। तिब्बतियों और अन्य लोगों के संरक्षित अधिकारों का सम्मान करने के अपने दायित्वों का पालन करने के अलावा चीन को तिब्बती पहचान को कमजोर करने वाली अपनी विलयवादी गतिविधियों को तुरंत बंद करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा चीन की समीक्षा से कई महीने पहले तिब्बती ब्यूरो जिनेवा ने केंद्रीय तिब्बती महिला संघ और स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय के साथ मिलकर जुलाई २०२३ में तिब्बत में मानवाधिकारों के व्यवस्थित और व्यापक उल्लंघन के पैटर्न का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सिफारिशें करने के अलावा तिब्बती संस्कृति पर चीनी सरकार की दमनकारी नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल, तिब्बती पहचान और भाषा का चीनीकरण, धार्मिक स्वतंत्रता पर दमनात्मक कार्रवाई, विभिन्न राष्ट्रीयताओं का दमन, निगरानी प्रणाली, तिब्बती पर्यावरण का विनाश और मनमानी गिरफ़्तारियां शामिल है।

चीन ने पिछले साल फरवरी में वैश्विक आवधिक समीक्षा से पहले आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कार्यान्वयन समीक्षा के अपने तीसरे चक्र को पूरा किया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने चीन द्वारा व्यापक उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए अपनी निष्कर्षात्मक टिप्पणियों के साथ चीन की समीक्षा की। इसमें अनुरोध किया गया कि पीआरसी सरकार तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के संचालन और तिब्बतियों के बड़े पैमाने पर पुनर्वास के अपने कार्यक्रम को तुरंत बंद कर दे और तिब्बतियों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करे।

वैश्विक आवधिक समीक्षा या यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) एक

ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को हर पांच साल में अन्य सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यूपीआर का उद्देश्य रचनात्मक आलोचना करना और हर देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुपालन के लिए सिफारिशों की जांच सुनिश्चित करना है। चीन की पिछली यूपीआर ०६ नवंबर २०१८ को की गई थी।

## ◆ मैनपाट तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी के नेतृत्व में सामुदायिक प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री से मुलाकात की

tibet.net, ०८ जनवरी २०२४

**मैनपाट।** मैनपाट तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी (टीएसओ) छेवांग यांगत्सो के नेतृत्व में स्थानीय तिब्बती सभा और सहकारी समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने ०५ जनवरी २०२४ को छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मुख्यमंत्री निर्वाचित किए जाने पर बधाई दी और उपहार में बुद्ध की एक थंगका पेंटिंग भेंट की।

यांगत्सो ने उन्हें सेटलमेंट के लिए भूमि की समस्या और तिब्बती पुनर्वास नीति २०१४ के कार्यान्वयन सहित प्रमुख चिंताओं से अवगत कराया।

सीटीए के दृष्टिकोण के अनुसार, सेटलमेंट सहकारी समिति नए आर्थिक अवसरों का निर्माण कर तिब्बती बस्तियों के भरण-पोषण की योजना पर काम कर रही है। नए आर्थिक अवसरों में सेंटलमेंट को पर्यटक हॉटस्पॉट बनाना, वहां आवास, रेस्तरां और दुकानों का निर्माण करना शामिल है। टीएसओ ने राज्य के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को इस बारे में अवगत कराने की बात कही और भविष्य में स्थानीय लोगों की ओर से किसी तरह के विवाद को रोकने के लिए समर्थन मांगा।

उसी दिन टीएसओ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सेटलमेंट की अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और राज्य के राजस्व विभाग के सचिव भुवनेश यादव से भी मुलाकात की।

एक दिन पहले ०४ जनवरी २०२४ को बस्ती भ्रमण करने आए छत्तीसगढ़ के नए विधायक राम कुमार टोप्पो का सेटलमेंट कार्यालय और वहां के निवासियों की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दौरे पर आए विधायक ने अपने भाषण में हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया और टीएसओ द्वारा उन्हें सेटलमेंट की कल्याणकारी चिंताओं से अवगत कराया गया।

## ◆ चीनी संपर्क अधिकारी छुल्ट्रीम ग्यात्सो ने 'अहिंसक प्रतिरोध, हाई-टेक अधिनायकवाद और चीन का भविष्य' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया

tibet.net, २४ जनवरी २०२४

**वाशिंगटन डीसी।** वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय में चीनी संपर्क अधिकारी छुल्ट्रिम ग्यात्सो ने १९ से २१ जनवरी २०२४ तक आयोजित 'अहिंसक प्रतिरोध, हाई-टेक अधिनायकवाद और चीन का भविष्य' विषयक पर संगोष्ठी में भाग लिया।

प्रसिद्ध चीनी वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता टेंग बियाओ ने उस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। संगोष्ठी का आयोजन विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन, चाइना एक्शन और इंस्टीट्यूट फॉर चाइना डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। संगोष्ठी में अनेक चीनी शिक्षाविद, लेखक और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख चीनी शोधकर्ता पेरी लिन, हूपिंग में लोकतंत्र समर्थक पत्रिका बीजिंग स्प्रिंग के संपादक प्रो. कैक्सिया, आईपीके मीडिया के संस्थापक वांग रुइकिन, जाने-माने उग्युर कार्यकर्ता इल्शात कोकबोरे और तियानमेन चौक नरसंहार में जीवित बचे रोज़ टैंग शामिल थे। इन सबको आगामी आंदोलनों और अभियानों पर चर्चा करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया गया था। सभा में परम पावन दलाई लामा के बारे में भी बहुत बातें की गईं और उन्हें अहिंसक आंदोलनों के आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया।

अपने संबोधन में चीनी संपर्क अधिकारी छुल्ट्रिम ग्यात्सो ने कहा कि परम पावन दलाई लामा का अहिंसक दर्शन दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से करने का मौलिक चिंतन है। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि परम पावन के मार्गदर्शन के अनुसार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में तिब्बती लोगों पर चीन के उत्पीड़न का विरोध करने

के लिए निर्वासित तिब्बतियों द्वारा कई तरह की अहिंसक पहल की जा रही है। तिब्बती प्रतिनिधि ने उसी समय संगोष्ठी में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बती भाषा और संस्कृति को मिटाने के प्रयासों के बावजूद तिब्बती पहचान के प्रचार और संरक्षण में तिब्बती लोगों की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख किया। संगोष्ठी स्थगित होने से पहले सम्मेलन के प्रतिभागियों ने भविष्य के कार्यक्रमों पर सहयोग जारी रखने को लेकर सहमति व्यक्त की।

## ◆ तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों ने कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से तिब्बती कल्याण जारी रखने का आग्रह किया

tibet.net, २५ जनवरी, २०२४

**बायलाकुप्पे।** लुगसुंग सैमडुपलिंग और डेक्यी लार्सो तिब्बती सेटलमेंट के अधिकारियों ने २४ जनवरी को बायलाकुप्पे स्थित संभूत तिब्बती स्कूल में कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया का स्वागत किया। सिद्धारमैया कोप्पा शहर का आधिकारिक दौरा करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर स्कूल के खेल के मैदान पर उतरा।

मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार और राज्य के कृषि मंत्री श्री एन. चालुवराय स्वामी भी थे।

स्वागत समारोह के दौरान तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों ने राज्य सरकार के उच्चस्तरीय गणमान्य अधिकारियों से क्षेत्र में तिब्बती निवासियों के कल्याण की सुरक्षा के लिए प्रदान की जा रही सहायता को जारी रखने की सम्मानपूर्वक अपील की। दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री को लुगसुंग सैमडुपलिंग और डेक्यी लार्सो तिब्बती सेटलमेंट के निवासियों की शिकायतों वाला एक ज्ञापन सौंपा।

## ◆ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की, तिब्बत के पक्ष में बात की

tibet.net, ३० जनवरी, २०२४

**धर्मशाला।** निर्वासित तिब्बती संसद के सरकारों को तिब्बत के समर्थन के लिए तैयार करने की पहल के हिस्से के रूप में सांसद गेशे न्गावा गांगरी और तेनज़िन चोएज़िन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में इस पक्षधरता कार्यक्रम के प्रयासों की शुरुआत की।

भोपाल पहुंचने पर तिब्बती सांसदों का भारत-तिब्बत मैत्री संघ के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। २६ जनवरी को भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के श्री गिरिराज किशोर, श्री राधे महाराज, श्रीमती अनीता जी और अन्य सदस्यों ने सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य तिब्बती सांसदों का स्वागत करना, उनकी चर्चा में शामिल होना और शहर के भीतर उनके एडवोकेसी कार्यक्रमों की योजना बनाना था।

इसके बाद श्रीमती भोपाल की महापौर मालती राय के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसदों ने तिब्बत की वकालत की और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके बाद उनकी मुलाकात गुफा मंदिर के (महंत) श्री श्री राम प्रवेश दासजी महाराज से हुई।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य श्री दिनेश यादव द्वारा सांसदों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की गई। मुलाकात के दौरान उन्होंने पंडित भंवर लाल शर्मा को शुभकामनाएं दीं और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की कार्यप्रणाली से परिचित कराया।

मध्य प्रदेश सरकार ने आवास और परिवहन की सुविधा प्रदान की।

प्रतिनिधिमंडल २७ जनवरी २०२४ को भोपाल में एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पहुंचा। यहां ५०० से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए तिब्बती सांसदों ने चीन-तिब्बत संघर्ष और तिब्बत में वर्तमान खतरनाक स्थिति के जटिल स्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लगातार समर्थन की अपील करते हुए तिब्बत और तिब्बतियों के प्रति अटूट समर्थन और एकजुटता के लिए भारत और यहां के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष ने संस्थान में १० तिब्बती छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सीटें आरक्षित करने की घोषणा की।

इसके बाद उन्होंने भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सुनी पांडे से शिष्टाचार मुलाकात की। अपनी बैठक के दौरान सांसदों ने तिब्बत के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर से मुलाकात करने की भी इच्छा व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने चीन-तिब्बत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। इसके बाद वार्ड दो की पार्षद/प्रधान श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी द्वारा दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई।

तिब्बती सांसदों ने भोपाल के एक्स-आर्मी एसोसिएशन के लोगों से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त तिब्बती लोगों के आंदोलन को समर्थन देने के रास्ते तलाशने के लिए भोपाल में बौद्ध समुदाय के प्रतिनिधि भी उनके साथ शामिल हुए। बैठक स्थानीय बौद्ध समुदाय की एकजुटता को बढ़ाते हुए तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को बौद्ध विहार आने के निमंत्रण के साथ संपन्न हुई।

प्रतिनिधिमंडल ने २८ जनवरी, २०२४ को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक के दौरान तिब्बती सांसदों ने उपमुख्यमंत्री को तिब्बत के अंदर की मौजूदा गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी और दस्तावेजों के आधार पर भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर जोर दिया।

चीन-तिब्बत संघर्ष और तिब्बत में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सांसदों ने २६वें डिजिआना-आईईएस इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट २०२४ की चर्चा में भाग लिया। उन्होंने आठवें अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अन्य विषयों के अलावा तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्व पर बात की। महोत्सव में प्रतिनिधिमंडल की बातचीत भारत समेत आठ देशों के बौद्ध समुदाय के सदस्यों के साथ हुई।

इन आयोजनों के बाद प्रतिनिधिमंडल का संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने परमहंस संत हिरदाराम साहिबजी (१९०६-२००६) के आश्रम का दौरा किया। इसके बाद सांसदों ने भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) की लगभग १५ महिला सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद एक सार्वजनिक चर्चा हुई, जिसमें डॉ. बी.आर. आंबेडकर के लगभग ३०० भारतीय बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया। इस सत्र के दौरान उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का परिचय दिया और दोनों समुदायों के बीच संबंध मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

## ◆ कैलाश शिखर के पास चीन का नया बांध भारत के लिए खतरा?

tibetanreview.net, २३ जनवरी, २०२४

ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने सुदूर पश्चिमी तिब्बत में एक नए बांध का निर्माण पूरा कर लिया है। newsweek.com द्वारा २२ जनवरी को उपग्रह चित्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट की यह बात अगर सच है तो वह नेपाल और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला होगा।

मापचा सांगपो नदी का तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका तिब्बत में अर्थ 'मोर' होता है। यह नदी भारत में घाघरा और नेपाल में करनाली के नाम से जानी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पश्चिमी नेपाल और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण और बारहमासी स्रोत है।

यूरोपीय संघ के कोपरनिकस अर्थ ऑबजर्वेशन प्रोग्राम के सेंटिनल-२ उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों को लेकर चलाने वाले सिनर्जिस की सेंटिनल हब वेबसाइट के फोटो विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि मापचा सांगपो पर बांध निर्माण जुलाई २०२१ में शुरू हो गया था।

ऐसा कहा जाता है कि यह बांध बुरांग शहर (तिब्बती: पुरांग) के उत्तर में बनाया गया है, जो तिब्बत के न्गारी प्रिफेक्चर में अनेक धर्मों के लिए पवित्र कैलाश पर्वत का इलाका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डैम अब पूरा हो गया है और इस महीने पृथ्वी की कक्षा से ली गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है।

कंक्रीट की संरचना नेपाल के सीमावर्ती शहर हिल्सा से लगभग १८ मील उत्तर में और भारतीय सीमा से लगभग ३७ मील पूर्व में है। हिल्सा की आबादी लगभग ५१,००० हैं, लेकिन नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र की आबादी ४० लाख से अधिक की है।

नेपाल के बाद मापचा सांगपो भारत के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जहां इसे सरयू के नाम से जाना जाता है और भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में पवित्र शहर अयोध्या से होकर गुजरती है। इस नदी को मोर की चोंच जैसे चट्टानी मार्ग से बहने के कारण मापचा सांगपो कहा जाता है, जिसका तिब्बती भाषा में मतलब मोर होता है।

चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा बीजिंग बुरांग उत्तर में एक और बांध बना रहा है, जिसका निर्माण दिसंबर २०२२ में शुरू हुआ था। यह परियोजना मापचा सांगपो से ऊपर की ओर तिब्बत की नदी प्रणाली को और बाधित कर सकती है।

हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को विशेष तौर पर उठाने वाली पत्रिका 'द थर्ड पोल' के दक्षिण एशिया मामलों के प्रबंध संपादक ओमैर अहमद ने न्यूजवीक को बताया कि तिब्बत में नए बांध में दक्षिण-पूर्व एशिया के मेकांग डेल्टा में चीन की जल-राजनीति की झलक मिलती है। अहमद ने कहा, 'इसकी सबसे अच्छी तुलना यह है कि कैसे चीन ने मेकांग में जल-राजनीति को नया आकार देने की कोशिश की है। यहीं पर उसने तर्क को तेजी से आगे बढ़ाया है कि ऊपरी इलाके के देशों को यह अधिकार है कि उसका सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पूरी तरह से खिलाफ होने के बावजूद निचले इलाके के पड़ोसी देशों को उसका सम्मान करना चाहिए। अहमद ने कहा, 'लेकिन मेकांग के विपरीत, दक्षिण एशिया में मेकांग नदी आयोग जैसा कोई क्षेत्रीय जल संस्थान नहीं है। इसलिए इसमें शामिल होने के लिए उनके पास कोई स्थान भी नहीं है।'

इस बीच, ध्यान देने वाली बात यह है कि तिब्बत में बहने वाली अंतरराष्ट्रीय नदियों पर बांध बनाने का चीन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि २०२१ में चीन ने तिब्बत की नदी प्रणालियों को मुख्य भूमि के बाकी हिस्सों से जोड़ने की योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत भारतीय सीमा क्षेत्रों पर एक दानवाकार बांध का निर्माण भी शामिल होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत ने चीनी निवेश वाली कंपनियों से बिजली खरीदने से इनकार करके चीन की जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध किया है, जैसे कि बीजिंग की वित्तीय सहायता से बना नेपाल में चामेलिया जलविद्युत स्टेशन।

चीन ने इस भू-रणनीतिक रूप से संवेदनशील तिब्बती सीमा क्षेत्र में एक नया अली पुलान हवाई अड्डा भी बनाया है, जो एक दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा है। यहां से नागरिक और सैन्य-दोनों तरह की गतिविधियां संचालित की जा सकती है। तिब्बत क्षेत्र के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आधिकारिक तौर पर पिछले महीने के अंत में चालू हो गया। अली-पुलान न्गारी-पुरांग में ही बन रहा है। न्गारी एक प्रिफेक्चर है जिसमें पुरांग नामकी काउंटी है।

## ◆ तिब्बत का सफाया : चीन की नवीनतम भाषाई लड़ाई

thejapurdialoges.com, ०९ जनवरी २०२४

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की सरकार तिब्बत को विश्व इतिहास के पटल से मिटाने पर आमादा है! एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण कदम के तौर पर चीनी सरकार अब अपने किसी भी आधिकारिक अंग्रेजी विज्ञप्ति में 'तिब्बत' शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि तिब्बत के बजाय 'ज़िज़ांग' कहा जाएगा।

'चीन के नस्लीय अल्पसंख्यकों को मूल चीनी के साथ एकीकृत करने' की

आड़ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि दुनिया स्वतंत्र तिब्बत के अस्तित्व को ही भूल जाए! आइए इस भाषाई परिवर्तन के पीछे पीआरसी की प्रेरणाओं और दुनिया पर इसके संभावित परिणामों पर चर्चा करते हैं।

***तिब्बत का सफाया***

चीनी अधिकारी १९४९ में तिब्बत पर कब्जे के बाद से मुख्य रूप से अंग्रेजी संचार में तिब्बत को इसी नाम से संबोधित करते रहे हैं। यह कदम पश्चिमी परंपराओं के साथ तालमेल दिखाने के लिए था। इसके अलावा, इस कदम ने परतंत्र हो गए तिब्बतियों के दिलों में तिब्बत की स्वतंत्रता के छोटे दीपक को प्रज्वलित रहने दिया।

हालांकि, चीनियों ने हाल ही में इस क्षेत्र को 'ज़िज़ांग' कहना शुरू कर दिया है। यह तिब्बत के लिए मंदारिन में मानक चीनी अनुवाद है। इस प्रकार, राष्ट्रपति शी की सीसीपी का इस कदम से स्वतंत्र तिब्बतियों को उनकी वास्तविक पहचान के किसी भी दावे से वंचित करने का लक्ष्य है। एक विलक्षण राष्ट्रीय पहचान के लिए अपने छद्म प्रयास में सीसीपी राष्ट्र के भीतर हान नस्ल की श्रेष्ठता और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, ज़िज़ांग के उपयोग चीन में घरेलू स्तर तक सीमित नहीं होगा। सीसीपी जल्द ही वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में शामिल अपने साझेदार देशों पर भी इसी शब्द का उपयोग करने के लिए दबाव डाल सकती है! विशेषज्ञों का आकलन है कि तिब्बत का उपयोग करने वाली संस्थाओं के खिलाफ आर्थिक दबाव और बहिष्कार सहित जबरदस्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है।

***चीन की जनसांख्यिकीय क्रूरता***

तिब्बत पर कब्जे के बाद से सीसीपी की सरकार ने १२ लाख से अधिक तिब्बतियों को मार डाला है! चीनी ड्रैगन द्वारा तिब्बती भूमि पर इस ज़बरदस्ती कब्जे पर दुनिया के शांति समर्थक चुप हैं! सीसीपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि तिब्बत उसके समर्थन में आ जाए, क्षेत्र में जान-बूझकर जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव कर दिया है। चीन ने क्षेत्र की कहानी को नया रूप देने के लिए इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुख्य भूमि के चीनी लोगों को फिर से बसाया है। इस तरह उसने तिब्बत की मूल संस्कृति को मिटाने का काम कर रहा है। मूल तिब्बती भाषा को प्रतिबंधित कर दिया गया है और बौद्ध जड़ों को उखाड़ दिया गया है! कई बौद्ध मंदिरों पर सीसीपी ने कब्ज़ा कर लिया है!

इस प्रकार, सीसीपी की कोशिश नाम में परिवर्तन कर तिब्बत पर अपना शासन मजबूत करने की है! इसके अलावा, सिमेंटिक स्विच तिब्बत की आजादी की लड़ाई पर वैश्विक कथानकों को नया आकार देने के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों के एक नया मोर्चा खोल रहा है। जल्द ही, चीनी तिब्बती शरणार्थियों को अलगाववादियों के रूप में प्रचारित करेंगे! वे इस कथ्य को प्रसारित करेंगे कि तिब्बत कभी भी एक अलग राष्ट्र नहीं था। वे लंबे समय से गुलाम बने इस राष्ट्र और इसके लोगों को किसी भी ऐतिहासिक या क्षेत्रीय पहचान से वंचित कर देंगे। जो लोग तिब्बत शब्द के उपयोग को चुनौती देंगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन समर्थकों द्वारा छिछालेदर की जाएगी!

***विचारणीय बिंदु***

असलयित यह है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भी काम कर रही है। दलाई लामा तिब्बती राज्य के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख हैं। दोनों इस प्रयास पर सहमत हैं कि तिब्बत पर अपने दावे को वैध बनाने के लिए चीन भाषाई बकवास का तरीका अपना रहा है।

तिब्बत को ज़िज़ांग कहनेकी चीन की जिद को भाषाई परिवर्तन से कहीं अधिक माना जाना चाहिए! यह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। चूंकि पीआरसी विश्व स्तर पर कथानकों को नियंत्रित करना चाहता है, इसलिए आशंका है कि अगले कुछ दिनों में भारत को भी अपने शत्रु पड़ोसी से अरुणाचल प्रदेश का नया नाम सुनने को मिल सकता है। सीसीपी तिब्बत को भाषाई युद्ध के मैदान में ले गई है और तिब्बत निश्चित रूप से क्षेत्र में सीसीपी की घृणित महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबंधित करने में विफल रहेगा। इस प्रकार, चीन के हाथों अपनी ज़मीन खोने के ७५ साल बाद तिब्बत विश्व इतिहास से अपना नाम मिटने का गवाह बन सकता है!

क्या दुनिया निष्पक्ष भाव से देखती रहेगी, क्योंकि पीआरसी इस भाषाई पैंतरेबाज़ी के माध्यम से अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का संकेत दे रहा है? तिब्बत के अंतिम अवशेषों को जलाते समय चीनी ड्रैगन के रास्ते में कौन खड़ा होगा?!!? इन प्रश्नों के उत्तर की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। आइए आशा करें कि ज़िज़ांग नाम तिब्बत के ताबूत में आखिरी कील साबित नहीं होगी!

## ◆ नास्तिक चीन को दलाई लामा के पुनर्जन्म मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए

thejapantimes.co.jp, २९ जनवरी २०२४

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने १९५० में तिब्बत पर कब्जे के बाद से तिब्बती धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ लगातार छेड़छाड़ किया है। इसमें १४वें दलाई लामा तेनज़िन ग्यात्सो के पुनर्जन्म को पहचानने की प्रक्रिया शामिल है। परम पावन अब ८८ वर्ष के हो चुके हैं और उनकी अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता के कारण उनके अनुयायियों की दुर्दशा को वैश्विक मंच पर जीवंत बनी हुई है।

बौद्धों का मानना है कि एक सम्यकत्व को प्राप्त जीव और अत्यधिक साधना सम्पन गुरु लोक कल्याण के लिए पुनर्जन्म धारण कर सकता है। तिब्बत में इसे टुल्कु के नाम से जाना जाता है और यह प्रणाली वहां की धार्मिक संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है। पुनर्जन्म लेने वाले गुरुओं में तिब्बतियों द्वारा सर्वोच्च आदर और सम्मान पाने वाले गुरुओं में दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक धर्मगुरु या लामा हैं।

दलाई लामा नामक तिब्बती संस्कृति के इस मूलभूत संस्था पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने और पुनर्जन्म प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए चीन ने २००७ में आदेश संख्या-५ और पिछले वर्ष आदेश संख्या-१९ जारी किया। ये कानून सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद-१८ और चीनी संविधान के अनुच्छेद-३६ का घोर उल्लंघन हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देते हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से नास्तिक मत की है और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में उसका कोई विश्वास नहीं है। १९५० के दशक में

१४वें दलाई लामा के साथ अपनी शुरुआती बैठकों में से एक के दौरान माओत्से तुंग ने कहा था कि 'धर्म अफीम है।' इसके तुरंत बाद चीन ने पूरे तिब्बत में ६००० से अधिक मठों और भिक्षुणी विहारों को नष्ट करना शुरू कर दिया। धार्मिक उत्पीड़नों की निरंतरता के कुछ उदाहरणों में २०१६ में बुद्ध की मूर्तियों का ध्वंस और २०१९ में लारुंग गार एवं याचेन गार जैसे विश्वविख्यात मठों को बंद करना तथा २०२१ में ड्रेगो मठ के स्कूल का विध्वंस शामिल हैं।

दुनिया शीर्ष तिब्बती धार्मिक धर्मगुरुओं में से एक ११वें पंचेन लामा के लापता होने से भी अवगत है। यह सबको पता है कि कैसे चीन ने १९९५ में अपने द्वारा एक कठपुतली को पंचेन लामा के पद पर बैठा दिया है और कैसे वह तिब्बतियों को इस फर्जी पंचेन लामा की पूजा करने के लिए मजबूर कर रहा है।

लामाओं के पुनर्जन्म के चयन पर अधिकार होने का चीन का दावा बेतुका है। चीन ने आधिकारिक आदेशों, उद्घोषणाओं, सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लेखों की एक शृंखला के माध्यम से प्राचीन रिवाजों पर अपने दावे को पेश करते हुए पुनर्जन्म प्रणाली पर अधिकार की पुष्टि की है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, 'पारंपरिक चीनी कानून में उपाधियों को शाही प्रशस्ति के रूप में समझा जाता है, यानी ये चीन की केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक संप्रदायों के गुरुओं को दी जाने वाली 'मानद उपाधियां' हैं। हालांकि, ऐसे दावे इतिहास के विकृत अध्ययन पर आधारित हैं।

सबसे पहले, इनमें से अधिकांश उपाधियां युआन (१२७१-१३६८) और किंग (१६४४-१९१२) शासन के दौरान दी गई थीं। चूंकि दोनों राजवंश चीनी नहीं थे, इसलिए इनके शासन को चीनी केंद्रीय सरकार कहना गलत और संदर्भ से बाहर है। चीन तब मंगोल युआन और उसके बाद मंचू किंग राजवंश के कब्जे वाला क्षेत्र ही कहा जाता था।

दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रणाली १४वीं और १५वीं शताब्दी की है, जब प्रथम दलाई लामा गेदुन द्रुपा के अवतार के रूप में दूसरे दलाई लामा गेदुन ग्यात्सो का जन्म १४७५ में हुआ था। यह प्रणाली वर्तमान तिब्बती परंपरा तक जारी है। बौद्ध नेता और चीन का यह दावा कि उसने प्राचीन काल से इस प्रक्रिया को संचालित किया है, पूरी तरह से झूठ है।

उस समय चीन पर शासन करने वाले मिंग राजवंश (१३६८-१६४४) के सम्राट द्वारा तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को पहली बार दलाई लामा की उपाधि नहीं दी गई थी। यह मंगोल राजा अल्तान खान था, जिसने सोनम ग्यात्सो से शिक्षा प्राप्त करने के बाद १५७८ में दलाई की उपाधि दी, जिसका अर्थ है 'ज्ञान का सागर'। बदले में आध्यात्मिक धर्मगुरु ने अल्तान खान को धर्म राजा की उपाधि से अभिषिक्त किया था। इससे पता चलता है कि मानद उपाधियों की पेशकश एकतरफा थोपना नहीं था बल्कि यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया थी, जिसका मतलब इस मामले में तिब्बती गुरु और मंगोल शासक के बीच सद्भावना और राजनयिक शिष्टाचार का संकेत था।

१७९२ में जब तिब्बत ने नेपाल की हमलावर गोरखा सेना को खदेड़ने के लिए किंग शासकों की मदद मांगी थी। तब मंचू सम्राट ने तिब्बत के प्रभावी प्रशासन के लिए २९ बिंदुओं का एक कानूनी संहिता लिखी थी। यह सुझाव दिया गया कि दलाई लामा और पंचेन लामा के पुनर्जन्मों का चयन 'स्वर्ण कलश' से नाम निकालकर किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक आदेश से अधिक सलाह के रूप में आया और १९वीं शताब्दी के मध्य में ११वें दलाई लामा के चयन को छोड़कर आगे इस पद्धति का उपयोग कभी नहीं किया गया।

चीन ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि पुनर्जन्म वाले जीवित बुद्धों को देश के भीतर ही खोजा जाना चाहिए, स्वर्ण कलश का उपयोग करके चुना जाना चाहिए और केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ है कि तिब्बत के बाहर के सभी लोग अयोग्य हैं। लेकिन टुल्कू का पुनर्जन्म कहीं भी हो सकता है। यह निर्णय लेना खुद पुनर्जन्म लेनेवाले लामा पर ही निर्भर करता है। भारत, नेपाल, मंगोलिया, भूटान और अन्य देशों में कई लामाओं का पुनर्जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए, चौथे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में और छठे का जन्म भारत में हुआ था।

इस दुनिया से प्रस्थान करने से पहले उच्च लामा अपने करीबी सहयोगियों या एक निर्दिष्ट समिति को संकेत छोड़ते हैं कि उनका पुनर्जन्म कहां पर हो सकता है। समिति तब बताए गए क्षेत्र में पैदा हुए बच्चों की तलाश करती है और संभावित लामा पर अध्ययन और परीक्षण करने के बाद पुनर्जन्म की पुष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया में देवताओं के साथ परामर्श सहित पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं।

सितंबर २०११ के अपने एक बयान में १४वें दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि उनका पुनर्जन्म उनकी पसंद पर निर्भर करेगा और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पुष्टि की कि पुनर्जन्म का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए आध्यात्मिक कार्य जारी रखना है। इसलिए यदि उनका पुनर्जन्म ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां स्वतंत्रता प्रतिबंधित है तो पुनर्जन्म का मूल उद्देश्य खो जाएगा। इसलिए, दलाई लामा का पुनर्जन्म एक स्वतंत्र देश में ही होगा।

२०१९ में अंतरराष्ट्रीय तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों और तिब्बती धार्मिक संप्रदायों के प्रमुखों ने निर्वासित तिब्बती सरकार के भारत के धर्मशाला स्थित मुख्यालय में मुलाकात की और सर्वसम्मति से चीन से पुनर्जन्म मुद्दे से दूर रहने की अपील की थी। इसी तरह के बयान जापान, भारत, वियतनाम और यूरोप में तिब्बती समूहों से आए हैं।

अमेरिकी सरकार ने अपने २०२० के तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम में स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्जन्म मुद्दे पर चीन के किसी भी हस्तक्षेप का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाएगा।

बीजिंग के लिए बेहतर होगा कि वह तिब्बती लोगों का दिल जीतने के लिए उन्हें डराने-धमकाने और धमकियां देने के बजाय गर्मजोशी भरा रुख अपनाए। जहां तक १५वें दलाई लामा के चयन की बात है, केवल तिब्बतियों की मान्यताओं के प्रति सम्मान और समझ से ही वास्तविक सद्भाव पैदा होगा। इसके विपरीत, उनके आध्यात्मिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप उन्हें बीजिंग से और दूर कर देगा।

***छेवांग ग्यालपो आर्य परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय में जापान और पूर्वी एशिया के प्रतिनिधि हैं। वे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत नीति संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार जरूरी नहीं कि सीटीए के तिब्बत नीति संस्थान के विचारों के अनुरूप हों।***

# IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

**Tenzin Jorden**
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

# आवश्यक सूचना

**प्रिय पाठकों,**

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

तेनज़िन जॉर्डन
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

**कार्यलय पताः** भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
**फोनः** 011–29830578
**ई–मेलः** coordinator@indiatibet.net

Regd No. : RNI 34636-79

January, 2024, Years: 45 Issue: 01

Tibet Advocacy Section
Department of Information and International Relations
Central Tibetan Administration
*12 January 2024*

# TIBET IN 2023

## CHINA'S HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

**Tibet** is the **least free region** in the world for the third consecutive year.

### JANUARY

Two Tibetans **Tatse and Dhonkho arrested** without reason.

Tibetans in Drakgo **warned not to share any information** on recent demolition.

Unknown number of **Tibetans died due to Covid** with **strict** Chinese regulation on **Information.**

### MARCH

Chinese police arrested **Yangtso for contacting Tibetans in exile.**

Tibetan **writer Zangkar Jamyang** known to have sentenced to 4 years.

Chinese police **stepped up its restrictions** on Tibetans during the anniversary of **10 March** and **14 March Tibetan uprising.**

### MAY

China **barred Tibetan writers, monks, and influential people** from conducting public talks.

**Sonam Gyatso** was released from prison in very **poor health.**

**Mining accident** in Tibet by a Chinese company resulted in the disappearance of 6 Tibetans.

### JULY

Chinese police **canceled Kalachakra teaching** by Lama Kalsang Tashi Gyatso in Tsolho, Amdo.

Chinese authorities **beat and detained Tibetan youths** conducting trades during Horse racing event while allowing Chinese to carry on their trade.

### SEPTEMBER

Schools in Tibet's **Karze and Ngaba ordered to ban Tibetan language use** and Tibetan **teachers are marginalized into unemployment.**

**Eight Tibetans arbitrarily** arrested in Darlag for reportedly **collecting donations for religious offerings.**

Vice chairman of the "TAR" carried out propaganda work to **indoctrinate Tibetan monastics** in Nyenrong, Nagchu.

### NOVEMBER

Tibetans **Gyalo, Tsedho, Bhamo, and Kari** were **sentenced** to two years in prison **for religious activities.**

PRC government released its infamous "**White Paper" on Tibet** titled "CPC Policies on the Governance of Xizang in the New Era: Approach and Achievements."

Singer Golog Palden sentenced to **three years** in prison for **writing "patriotic song."**

### FEBRUARY

**New Cybersecurity Law** increases surveillance and censorship on Tibetans.

Tibetan political prisoner, **Geshe Phende Gyaltsen** died in prison due to Chinese police **torture.**

**Increased restrictions** and phone inspections during Tibetan **Losar celebration.**

### APRIL

**Gonpo Kyi** was **severely beaten** for protesting against China's unlawful sentencing of Dorjee Tashi to life imprisonment.

UN Rights Expert slammed China's mandatory vocational training programs and labour transfer.

### JUNE

Tibetans **forced to pay respect to the Chinese Panchen Lama.**

Tibetan **university** students compelled to give **entrance exam in Chinese language only.**

**Monks** of Shentsa and Sog County monasteries are **forced to denounce His Holiness the Dalai Lama.**

Officials clamped down on satellite equipments to **only allow government-approved channels.**

### AUGUST

**Tashi Wangchuk** was **attacked** by Chinese police for his **continued advocacy for the preservation of Tibetan language.**

Tibetan **writer Dhi Lhaden released** from prison after 4 years.

Former political prisoner, **Sonam Gyalpo, dies** at age 68.

Approx. **951 Tibetan herders forcibly relocated** from Damshung to Toelungdechen in the "TAR."

### OCTOBER

Chinese police **arrested Kunchok Dakpa and Wangchuk Tso** for allegedly contacting people outside the region and sharing pictures of His Holiness the Dalai Lama respectively.

A workshop in Tibet's Ngari mandated 400 teachers and students to support the CCP and denounce His Holiness the Dalai Lama.

Language rights advocate, **Tashi Wangchuk, denied business license and beaten by Chinese police.**

### DECEMBER

Tibetan women Tsomo and Nyidon arbitrarily arrested for **discussing Tibetan Buddhism on WeChat.**

Semkyi Dolma **imprisoned** for one and half years for **contacting Tibetans in exile.**

Rights defender Tsering Tso known to have subjected to 15-day "administrative detention" for **exposing Chinese police's racial discrimination against Tibetans.**

Fours Tibetans arrested for **engaging** in **religious activities.**